



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2001/आश्विन 18, 1923

No. 278]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2001/ASVINA 18, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2001

सं. टीएमपी/27/2001-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों से संबंधित दरों के मान के बारे में इस प्राधिकरण के दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के आदेश की समीक्षा करने के लिए एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निपटान करता है।

अनुसूची

(मामला सं० टीएमपी/27/2001-जेएनपीटी)

न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी)

आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 2001 के 20वें दिन पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों से संबंधित दरों के मान के संशोधन के लिए न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) के प्रस्ताव का निपटान करते हुए 7 नवम्बर, 2000 को एक आदेश पारित किया था।

2. एनएसआईसीटी ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दों के संबंध में आदेश की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है :-

- (i) तकनीकी सेवा शुल्क की अनुमति देना।
- (ii) प्रशुल्क निर्धारण हेतु लागत घटक के रूप में कर शामिल करना।

- (iii) नियोजित पूंजी पर आय ।
- (iv) विदेशी मुद्रा घाटे की अनुमति का आधार ।
- (v) विभिन्न आपरेटरों के लिए प्रशुल्क का एकसमान आधार लागू करना ।

3.1. एनएसआईसीटी ने उल्लेख किया है कि इसने संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उसे परामर्श देने के लिए मैसर्स आर्थर एंडरसन को नियुक्त किया है । एनएसआईसीटी ने मैसर्स आर्थर एंडरसन द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति भी भेजी है । प्रारंभ में एनएसआईसीटी ने मैसर्स आर्थर एंडरसन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की गोपनीय बनाए रखने और एनएसआईसीटी तथा मैसर्स आर्थर एंडरसन की लिखित अनुमति के बिना इस रिपोर्ट को प्रकाशित न करने का अनुरोध किया था ।

3.2. एनएसआईसीटी ने आर्थर एंडरसन रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया था, इसलिए यह सूचित किया गया कि रिपोर्ट पर तभी विचार किया जाएगा, यदि गोपनीयता बनाए रखने की शर्त को वापस ले लिया जाता है । यह आवश्यक था, क्योंकि इस मामले में एनएसआईसीटी के आवेदन-पत्र का विश्लेषण उक्त रिपोर्ट में व्यक्त विचारों के अनुसार कर आवश्यक था, यदि यह रिपोर्ट रिकार्ड में विचारार्थ ली जाती है । एनएसआईसीटी ने बाद में सूचित किया कि वे उक्त शर्त पर लागू गोपनीयता संबंधी शर्त वापस लेते हैं ।

4. इस याचिका को 'समीक्षा' मामले के रूप में पंजीकृत किया गया है । पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत मुद्दे प्रशुल्क वृद्धि निर्धारण में इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से संबंधित हैं । चूंकि, कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया है, इसलिए समीक्षा आवेदन पत्र संबंधित प्रयोक्ताओं को टिप्पणियों के लिए नहीं भेजा गया था ।

5.1. इस मामले में आरंभिक विचार करते समय, इस प्राधिकरण ने निर्णय किया था कि संदेहास्पद आदेश के आर्थर एंडरसन के विश्लेषण के संबंध में एनएसआईसीटी को उनके द्वारा कोई प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया था । एनएसआईसीटी के इस तर्क पर कि उनके मामलों में निवेश पर आय का नया दृष्टिकोण अपनाने से पूर्व निजी टर्मिनलों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का एक अवसर प्रदान नहीं किया गया था, तथापि विशेष रूप से विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया था कि एनएसआईसीटी द्वारा इंगित प्रक्रियागत चूक को निवेश पर आय के सीमित मुद्दे पर संयुक्त सुनवाई आयोजित करके ठीक किया जा सकता है, तत्पश्चात प्रस्तावित सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर पूरा ध्यान देते हुए मामले का अंतिम तौर पर निपटारा किया जा सकता है । यह भी निर्णय किया गया था कि उपलब्ध अवसर का न केवल विचाराधीन एनएसआईसीटी मामले बल्कि सभी निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क मामलों में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

5.2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, निजी टर्मिनलों को अनुमत्य निवेश पर आय से संबंधित मामले में एक संयुक्त सुनवाई एमबीपीटी परिसर में 3 सितम्बर, 2001 को निर्धारित की गई थी । एनएसआईसीटी के अलावा पतन प्रयोक्ताओं और व्यापार जगत के निम्नलिखित संगठनों/प्रतिनिधि निकायों को सुनवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था :-

- (1) पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल लिमिटेड ।

- (2) चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ।
- (3) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ।
- (4) तूतीकोरन पत्तन न्यास ।
- (5) मुरुगाव पत्तन न्यास ।
- (6) चेन्नई पत्तन न्यास ।
- (7) एबीजी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ।
- (8) भारतीय राष्ट्रीय पोतस्थामी संघ ।
- (9) कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन ।
- (10) भारत में माल अग्रेषक संगठनों का संघ ।
- (11) जहाजी कुलियों के संगठनों का संघ ।
- (12) भारतीय उद्योग महासंघ ।
- (13) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ ।
- (14) इंडियन मर्चेंट चैम्बर ।

6 संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे —

न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड

(चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का भी प्रतिनिधित्व किया)

- (i) बीओटी करार में कठोर अपेक्षाएँ हैं, जिन्हें किसी भी निजी आपरेटर को पूरा करना होता है ।
- (ii) कृपया पूँजी के विभिन्न स्रोतों की लागत अपनाने की बजाय नियोजित पूँजी पर आय की पद्धति अपनाई जाए ।
- (iii) यदि कर देयता को शामिल करना है तो कर-पूर्व आय पर्याप्त नहीं है ।
- (iv) हमारी मूल कंपनी ने जोखिम शामिल करते हुए ऋणों की गारंटी दी है । इसने जोखिम को एनएसआईसीटी पर ही डाला है । इसलिए, इक्विटी पर आय अधिक होगी ।
- (v) ऋण पर कर लाभ मिलते हैं । लेकिन, इक्विटी पर नहीं । कृपया इस अंतर पर विचार करें ।
- (vi) विदेशी मुद्रा घाटों पर विचार नहीं किया गया है ।
- (vii) तब अन्यत्र अप्रयुक्त पूँजी पर 20% की आय हम कैसे प्राप्त करेंगे ?
- (viii) पश्च-पैनामिक्स क्रैनों के बारे में सीएसएलए की टिप्पणियाँ, उनके द्वारा जो कुछ हमें कहा गया है, उसके अनुरूप नहीं हैं । जेएनपीटी चैनल को गहरा करने की योजना बना रहा है । हमें आगे देखना है ।
- (ix) इक्विटी, ऋण और प्रारक्षित निधि पर आय अवश्य प्राप्त होनी चाहिए ।

- (x) सीएसएलए ने आईआरआर और पूंजी पर आय के बीच भ्रम पैदा किया है । आईआरआर परियोजनाओं के बीच से चुनने के लिए है । आरओसीई किसी परियोजना विशेष के लिए होता है ।
- (xi) कृपया कोई कठोर ऋण-इक्विटी अनुपात न रखें । प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया जाए ।
- (xii) सभी ढांचागत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए समान मूल सिद्धांत हैं । उनके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है और उनसे आय धीमी होती है । इसलिए, आय की कोई गारंटी नहीं होती । आय की गारंटी होनी चाहिए । अन्यथा, कोई भी निवेश क्यों करेगा ?
- (xiii) बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लागू करने से कर-अवकाश संबंधी स्थिति बदल गई है ।
- (xiv) बीओटी छूट की अवधि समाप्त होने पर विदेशी इक्विटी के मूल्यहास पर टीएमपी द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन

- (i) यह अच्छा है कि टीएमपी इन ब्योरो पर विचार करता है ।
- (ii) कृपया, निजी टर्मिनलों की महापत्तन न्यासों से तुलना न करें । यद्यपि, निजी टर्मिनलों को अनुमत्य 20% की आय भी अधिक है ।
- (iii) प्रचालन के 10/15 वर्ष तक 20% की आय तर्कसंगत हो सकती है । लेकिन, शुरू में यह कम होनी चाहिए ।
- (iv) एनएसआईसीटी के मामले में अपनाया गया मॉडल गारंटीशुदा प्रशुल्क और अच्छी आय प्रदान करने में उदार है । यह टर्मिनल के लिए परोपकार का कार्य है ।
- (v) कृपया, 'लागन-वॉल्ट' मॉडल को समाप्त करें । यह एक गैर-आर्थिक और गैर-वाणिज्यिक दृष्टिकोण है । कृपया, निजी टर्मिनल को वाणिज्यिक जोखिमों से अलग न करें । इससे कार्यकुशलता में हानि होगी ।
- (vi) दूरसंचार क्षेत्र के साथ तुलना करने संबंधी एनएसआईसीटी का तर्क वैध नहीं है । दूरसंचार अत्यंत जोखिम वाली प्रौद्योगिकी है, पत्तन उस श्रेणी में शामिल नहीं है ।
- (vii) प्रशुल्क में विदेशी मुद्रा का घाटा होने से इसका डोलरीकरण होता है ।
- (viii) एनएसआईसीटी कार्यकुशलता के लिए भुगतान मांगेगा । वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के कारण इस क्षेत्र में आए हैं । वे उसके लिए अतिरिक्त वसूली नहीं करेंगे ।

मुंबई एवं न्हावा शेवा पोत एजेंट संघ

- (i) इक्विटी के साथ-साथ मुक्त प्रारक्षित निधियों पर भी विचार किया जाए ।
- (ii) महापत्तन न्यासों का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है । परंतु, निजी टर्मिनलों को लाभान्श का भुगतान करना होता है । इसलिए, उन पर अलग से विचार किया जाए ।
- (iii) आयकर अधिनियम की धारा 80 ज के अधीन नियोजित पूंजी के 15% की कटौती की गई थी । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दीर्घावधिक ऋणों को नियोजित पूंजी की परिभाषा से बाहर रखने के लिए नियोजित पूंजी को पुनः परिभाषित करने के वास्ते इस प्रावधान को संशोधित किया है ।
- (iv) 1:1 का ऋण-इक्विटी का अनुपात अत्यंत उदार है । ऐसा लगता है कि 2:1 का अनुपात अधिक सार्थक हो सकता है ।

भारत में माल अग्रेषक संगठनों का संघ

- (i) किसी महापत्तन न्यास और निजी टर्मिनल के बीच तुलना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है । वे अतुलनीय हैं ।
- (ii) 1:1 का ऋण-इक्विटी का अनुपात अत्यंत आकर्षक है ।
- (iii) प्रारक्षित निधि को आय के लिए क्यों माना जाए । इसकी कटौती की जाए ।
- (iv) विदेशी मुद्रा घाटा एक सामान्य वाणिज्यिक जोखिम है ।

इंडियन मर्चेण्ट चैम्बर (आईएमसी)

- (i) महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनलों के उद्देश्य अलग-अलग हैं । उनकी तुलना नहीं की जा सकती ।
- (ii) पत्तन मूल्य निर्धारण द्वारा कम लागत पर कुशल सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए ।
- (iii) व्यापार संबंधी जोखिम प्रशुल्क वृद्धि का आधार नहीं हो सकते । एनएसआईसीटी को व्यापार जोखिमों की पूरी जानकारी हो गई होगी ।
- (iv) मांग की तुलना में स्थापित क्षमता अधिक होगी चाहिए । मांग और आपूर्ति के बीच कोई कठोर समानता नहीं हो सकती ।
- (v) निजी टर्मिनल अपनी कार्यकुशलता के कारण शिपिंग लाइन्स को अनेक लाभ दे सकते हैं । उसे व्यापार जगत पर नहीं लादा जा सकता । इस स्थिति में कोई कार्यकुशल निजी टर्मिनल व्यापार जगत को कैसे लाभ दे सकता है ।
- (vi) खुली प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाए । पहले किए गए भारी निवेशों की पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए रक्षा की जाए ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

- (i) जेएनपीटी का शीघ्र ही निगमीकरण किया जाएगा । हम वाणिज्यिक होंगे और हमें भी लाभों की जरूरत होगी । हम अपनी आरओसीई को अधिकतम करना चाहते हैं ।

7.1 पीएसए एसआईसीएल ने इसके तृतीकोरन टर्मिनल में कुछ संकट होने के कारण संयुक्त सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता सूचित की थी । उसके 10 दिन के भीतर लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी । इसी प्रकार, एनएसआईसीटी, सीएसएलए, एमएएनएसए तथा एबीजी के और लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी । एनएसआईसीटी ने सीएसएलए, एमएएनएसए, आईएमसी और जेएनपीटी को आर्थर एंडरसन रिपोर्ट की एक प्रति भी परिचालित की थी ।

7.2 इन संगठनों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों में दिए गए प्रमुख मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है --

L ऋावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड

- (i) प्राधिकरण निजी निवेशकों के तुलन पत्र प्रबंध में विश्वास रखेगा, क्योंकि कोई भी निवेशक ऐसी स्थिति नहीं रखेगा, जिससे विश्वस्तरीय निवेशकों के होते हुए कंपनी को कोई हानि हो ।
- (ii) प्राधिकरण को यह निर्णय अवश्य करना चाहिए कि यदि नियोजित पूंजी क्षमता समुपयोजन की पर्याप्त परिचायक है और यदि ऐसा है, तब कंपनी को नियोजित पूंजी पर निर्धारित आय की अनुमति दी जानी चाहिए ।
- (iii) आय का निर्धारण करने के लिए अनेक मानक हैं, जिनका प्रयोग किया जा सकता है । आय का निर्धारण करने के लिए एक सर्वोत्तम मानक नियोजित पूंजी है, क्योंकि इसका नए निवेश दर्शाने और वर्तमान निवेशों

में कमी करने के लिए वर्ष-प्रतिवर्ष समायोजन किया जाता है। प्राधिकरण ने पत्तन न्यासों के मामले में इस मानक का सही चयन किया है और इस मानक को जारी रखना चाहिए।

- (iv) प्राधिकरण ने इक्विटी पर 20% आय को एक मानक के रूप में अपनाया है। यदि कर-अवकाश होता तब विदेशी निवेशक को केवल 9.08% की निवल आय होती है। यदि कोई कर अवकाश नहीं है, तब निवेशक को केवल 4.5% आय होती है।
- (v) प्राधिकरण को निजी टर्मिनलों के मामले में नियोजित पूंजी पर आय 20% से 25% की सीमा में अपनानी चाहिए।
- (vi) प्रश्न यह उठता है कि क्या बीओटी का प्रचालन करने वाली कंपनी विकास प्रारक्षित निधि और प्रतिस्थापन प्रारक्षित निधि के लिए पात्र है। बीओटी परियोजनाओं के अधीन कंपनियों के मामले में ये प्रारक्षित निधियां कंपनियों के बने रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लाइसेंस अवधि के अंत में ये कंपनियां अपनी सभी परिसंपत्तियां पत्तन न्यास को बिना किसी लागत के सौंप देती हैं और कर्मचारी की सभी देयताओं/भुगतानों को पूरा करती हैं, क्योंकि पत्तनों द्वारा इन कर्मचारियों का अपने यहां विलय नहीं किया जाता है। पत्तन को 7-10 वर्ष के प्रयोग के बाद उपस्कर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाते हैं, जबकि इनका जीवनकाल 20 वर्ष का होता है। ऐसे मामले में कंपनी को एक चतुर वित्तीय योजना की अपेक्षा होती है, जिससे वह अपने पास एक प्रारक्षित निधि रख सके, ताकि उससे वह भारी पूंजीगत व्यय को पूरा कर सके। उसे परिसंपत्तियों के उपयोगी आधे जीवन से अधिक हिस्से को बढ़ते खाते डालना पड़ सकता है। यदि मूल्यहास का दुगुना लगाया जाता है (क्योंकि बीओटी आपरेटर के लिए उपयोगी जीवनकाल सीमित है), तब आपरेटर के प्रशुल्क वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य हो जाएंगे, जिससे भारी वित्तीय हानि होगी। इस प्रकार, बीओटी आपरेटर को इन कठोर देयताओं का सामना करना पड़ता है, जोकि लम्बी अवधि में विस्तारित होनी चाहिए, ताकि परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, प्राधिकरण को अर्जित आय के कुछ प्रतिशत को विकास और प्रतिस्थापन के लिए प्रारक्षित निधि बनाने के लिए अनुमति पर विचार करना चाहिए।
- (vii) यह प्रश्न उठता है कि क्या ऋण-इक्विटी का 1:1 का अनुपात उपयुक्त अनुपात है। प्राधिकरण को पत्तन न्यासों के मामले में प्राधिकरण द्वारा सही चुने गए आय के लिए नियोजित पूंजी को आधार के रूप में मानना चाहिए। ऐसे परिदृश्य में ऋण-इक्विटी का अनुपात लागू नहीं होता। इसके अलावा, जबकि इक्विटी की पुनर्खरीद न होने के कारण शेरधारक निधियां सामान्यतया सतत बनी रहती हैं, तब वापसी अदायगी की समय-सारणी के आधार पर ऋण का पुनर्भुगतान किया जाता है। ऐसे मामले में ऋण कम होता जाएगा और इस प्रकार इक्विटी घटक सदैव अनुपात में बदला जाएगा तथा जब सारे ऋण का पुनर्भुगतान हो जाएगा, तब केवल इक्विटी घटक शेष रह जाएगा। प्राधिकरण को निजी निवेशकों को वित्तपोषण पैटर्न का निर्णय करने की अनुमति देनी चाहिए। यह कंपनी हितों के लिए हानिकारक नहीं होगा।

II. पीएसए एसआईसीएल लिमिटेड

- (i) टीएमपी ने ऋण और इक्विटी के लिए 1:1 के अनुपात का मानदंड निर्धारित किया है। ऋण और इक्विटी का अनुपात किसी प्रवर्तक की वाणिज्यिक अपेक्षाओं और उसकी धन जुटाने की क्षमता के अनुसार अलग-अलग आपरेटरों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसलिए, टीएमपी को ऋण-इक्विटी के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) टीएमपी ने क्षमता-समुपयोजन का मूल्यांकन के कारक के रूप में प्रयोग किया है। निजी टर्मिनलों के मामले में नई क्षमता अभिवृद्धि से सामान्यतया परिमाण में वृद्धि होगी। इसलिए, टीएमपी निजी आपरेटरों के व्यवसाय मॉडल की समीक्षा करते समय नम्यता प्रदान कर सकता है।
- (iii) टीएमपी ने 'कर-परच आय' की बजाय 'कर-पूर्व आय' का संकेतक के रूप में प्रयोग किया है। यदि देय कर को हिसाब में लिया जाता है, तब कर-अवकाश के प्रावधानों के अनुसार शेरधारक निधियों पर आय कम हो कर न्यूनतम 14% रह जाएगी। व्यवसाय जोखिमों को पूरा करने के लिए यह निश्चित है अपर्याप्त है।

- (iv) वस्तुतः शेयरधारकों की निधियों पर 20% की आय और ऋण पर ब्याज व्यवसाय प्रचालनों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है ।
- (v) दीर्घावधि में टीएएमपी विशेषकर कार्यकुशल प्रचालित टर्मिनलों के मामले में लागतवर्धित मॉडल से हटकर प्रतिस्पर्धी शुल्क मॉडल की ओर चला जाएगा । लागतवर्धित मॉडल कार्यकुशलत प्रचालन और उच्च संपत्ति समुपयोजन वाले निजी आपरेटरों के लिए हतोत्साहन है ।

III. एबीजी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- (i) प्रत्येक टर्मिनल आपरेटर को परियोजना की पूंजी संरचना में ऋण और इक्विटी के संयोजन का स्वयं निर्णय करने की अनुमति दी जानी चाहिए । प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वित्तपोषण ऋण के माध्यम से या इक्विटी जुटा कर किया गया है । परियोजना की संपूर्ण लागत नियोजित पूंजी के रूप में मानी जाएगी और पूंजी की 20% लागत को प्रशुल्क निर्धारण के लिए माना जाना चाहिए ।
- (ii) चूंकि, इक्विटी में परिसंपत्तियों की कोई सुरक्षा नहीं होती और जोखिमों तथा पुरस्कारों की अनिश्चितता का भय बना रहता है, इसलिए नियोजित पूंजी के इक्विटी घटक पर 20% की आय की अनुमति पूंजी की समग्र लागत पर दी जाएगी ।
- (iii) यदि सरल रेखीय प्रणाली पर मूल्यङ्कास किया जाए तो यह राशि पहले कुछ वर्षों में ऋण वापसी की राशि की तुलना में कुछ कम होगी । अतः, हमारी राय में मूल्यङ्कास पर विचार आवश्यक रूप से अवलेखन मूल्य प्रणाली द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे पहले कुछ वर्षों में मूल्यङ्कास से संबंधित बड़ी राशि उपलब्ध हो जाए जो मूलधन की वापसी की राशि के तुल्य होगी ।
- (iv) देनदारियों पर ब्याज कर-कटौती योग्य व्यय है जबकि इक्विटी पर प्राप्त आय को सिर्फ कर-पश्च लाभ में शामिल किया जाता है । अतः, इक्विटी पर आय के पूर्व कर को प्रशुल्क का हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है । यह खासकर धारा 80-आईए के अंतर्गत करावकाश कटौती की सीमित प्रयोज्यता तथा कंपनियों के लामांश वितरण पर कर देयता, जो पत्तन न्यासों के मामले में लागू नहीं होते, की दृष्टि से प्रासंगिक है ।
- (v) क्षमता उपयोग के मामले में प्रशुल्क निर्धारण के लिए जिस तथ्य पर अनिवार्यतः विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि पत्तन के अस्तित्व के विभिन्न चरणों में व्यवहार्य क्या है । अतः, परियोजना के प्रारंभिक निर्माणात्मक वर्षों में क्षमता उपयोग निर्धारित क्षमता के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से तब तक वृद्धि की जानी चाहिए जब तक कि यह 80% पर न पहुंच जाए ।

IV. कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन

- (i) सीएसएलए इस बात को ले कर चिन्तित है कि विकल्पों के अभाव के परिणामस्वरूप जो भी अर्जन निर्देश चिह्न स्थापित किया जाता है, वह मानदण्ड बन जाता है । इस प्रकार टर्मिनल आपरेटर व्यावसायिक जोखिमों (जब तक यातायात प्रवाह में अत्यधिक कमी न आ जाए, जो संभव नहीं प्रतीत होता) से कारगर ढंग से पृथक् हो जाता है और संभवतः गारंटीशुदा प्रतिफल पाने की सुखद स्थिति में पहुंच जाता है । सीएसएलए ऐसी व्यवस्था को प्राथमिकता देता है, जैसा कि आर्थर एण्डरसन की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.01 में वर्णित है और जिसमें यह कहा गया है, "संक्षेप में, यदि दर निर्धारण का समरूप आधार रखा जाता है तो कतिपय मानदण्डों पर पूर्व-निर्धारित स्तर के अंतर्गत वार्ता ढ़ी जा सकती है । ऐसा कोई कारण नहीं जिससे निर्धारित स्तर को सभी मूल्य निर्धारण का अनिवार्य आधार बनाया जाए । निजी टर्मिनल कम दरों पर वार्ता में सफल हो जाएंगे ।
- (ii) एनएसआईसीटी के वित्तीय आकड़ों (31.12.2000 को समाप्त अवधि तक 9 महीने के लेखा परीक्षित लेखे) के अन्वेषण से यह स्पष्ट होता है कि एनएसआईसीटी वर्तमानतः शेयरधारकों की इक्विटी पर 26% अर्द्ध (वार्षिक आधार पर) कर रहा है (जहां आय = करोपरास्त लाभ + तकनीकी सेवा शुल्क, मुक्त रॉयल्टी, और शेयरधारकों की इक्विटी = शेयर पूंजी + निर्बन्ध आरक्षित कोष)। आय की यह मात्रा अधिक पूंजी वाले उद्योगों में सामान्य

तौर पर संचित होने वाली मात्रा की तुलना में काफी अधिक है। अतः, हम यह जान पाने में असमर्थ हैं कि एनएसआईसीटी अब भी अपने निवेश पर अधिक आय की मांग क्यों कर रहा है।

- (iii) शेयरधारकों की इक्विटी पर आय, मूल्य विनियमन का एक सवेदनशील पैमाना है, जिससे आय करोपरान्त लाभ (किसी पार्टी को रॉयल्टी/तकनीकी सेवा शुल्क के भुगतान के समायोजन के बाद) के तुल्य हो जाएगा और शेयरधारकों की इक्विटी में शेयर पूंजी + निर्बन्ध आरक्षित कोष एवं अधिशेष शामिल होगा।
- (iv) यह विवाद कि निजी टर्मिनलों तथा पत्तन न्यासों के लिए मूल्य विनियमन की समान व्यवस्था होनी चाहिए, तर्कसंगत है बशर्ते कि दोनों के दायित्व समान हों। यह स्वीकार करना होगा कि पत्तन न्यासों के लिए कानूनी तौर पर कुछ सामाजिक एवं प्रचालनात्मक दायित्व हैं जो समान नहीं हो सकते, जैसे कि एनएसआईसीटी के दायित्व/व्यवस्था औचित्यपूर्ण एवं बाजार से सम्बद्ध भी होनी चाहिए। पत्तन न्यासों को स्वीकृत आय काफी अधिक है। इनमें अधोमुखी समायोजन किए जाने की जरूरत है और इसके बाद ही उपर्युक्त टिप्पणियों के अध्यक्षीन निजी तथा राजकीय टर्मिनलों के लिए समान व्यवस्था लागू की जाए। आय पत्तनों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर (जो चालू वर्ष में 13% है) तक सीमित होगी। किसी अन्य 'आरक्षित कोष' के लिए अतिरिक्त छूट की स्वीकृति नहीं होगी। इसका अर्थ यह होगा कि यदि एक बार आय 13% से अधिक हो जाए तो आपरेटर को प्रशुल्क में वृद्धि के लिए टीएमपी के पास आने की जरूरत नहीं होगी।
- (v) यह महसूस किया गया है कि 'लागत वर्धित' मूल्य निर्धारण प्रणाली पूरी तरह गलत है। इससे टर्मिनलों पर सुदृक्ष होने का कोई दायित्व नहीं रह जाता। इससे व्यापार, अथवा लाइनों या देश को कोई सतोषजनक सेवा प्राप्त नहीं हो सकेगी और वाणिज्यिक आत्मसंतोष तथा अवक्षता कायम हो जाएगी।
- (vi) एनएसआईसीटी तथा जेएनपीटी दोनों पर विदेशी मुद्रा ऋण है जिसकी भविष्यवाणी तथा अनुमान संभव है। भारतीय रुपए का अपवादात्मक तौर पर अवमूल्यन नहीं हुआ है और इसलिए विनिमय हानि को आपरेटरों का वाणिज्यिक जोखिम माना जा सकता है। यह भी दिलचस्प है कि टीएमपी ने प्रशुल्क (लागत की कतिपय मदों को छोड़कर) का भुगतान डॉलर में करने का नियम बनाया है। सभी मुद्राओं से संबंधित जोखिमों को दूर करने का यह प्रस्ताव डॉलर में प्रशुल्क भुगतान प्राप्त करने के प्रभाव के समान बनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है।
- (vii) दूरसंचार और विद्युत उत्पादन कारोबार से तुलना करना अनुपयुक्त है। पूर्ववर्ती उच्च जोखिम वाला नई प्रौद्योगिकी का कारोबार है। उत्पादों की अपेक्षतया कम "शेल्फ अवधि" होती है और इसलिए आय की उच्च दर का औचित्य हो सकता है। इसकी तुलना कटेनर टर्मिनल कारोबार, जो पुरानी और सुपरीक्षित प्रौद्योगिकी है और नया उद्योग नहीं है, से करना अनुपयुक्त है। विद्युत उत्पादन कारोबार से समानान्तर तुलना भी अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें अपेक्षतया कुछ सविदाकारी पार्टियां शामिल होती हैं, जिनमें से कई राज्य सगठन होते हैं।
- (viii) यह असाधारण प्रतीत होता है कि एनएसआईसीटी ने अपना लागत निर्धारण स्पष्टतया इतना गलत पाया कि उसके लिए विनियामक प्रणाली में और परिवर्तन की आवश्यकता हुई, जब उन्हें वर्ष 1998 में प्रशुल्क अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिसने समवतः पर्याप्त आय दी, में एक वर्ष बाद और परिवर्तन की अपेक्षा हुई और अब इसमें और समायोजन अपेक्षित है। ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि लागतें बढ़ गई हैं अथवा अन्य परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। आर्थर एडरसन ने सही कहा है कि अगर लागतें बढ़ती हैं, उनकी वसूली के लिए कोई कार्यतंत्र अवश्य होना चाहिए, बशर्ते निसंदेह कि कोई औचित्यपूर्ण मामला ऐसा करने के लिए बनाया जाए।
- (ix) स्वीकृत की गई किसी वृद्धि का परिणाम वर्धित टर्मिनल प्रहस्तन प्रभारों में वृद्धि होगा। यद्यपि व्यापार जगत को वापस क्षमताओं को देना लाइनों द्वारा यथा बुनियादी विफलता का सुझाव देना गलत है। यह लाइनों के बीच वर्धित प्रतिस्पर्धा द्वारा अब हो रहा है, जो यूरोपीय व्यापार के मामले में नाटकीय रूप से (4 महीनों में प्रति टीईयू 1300 से 550) मालमाड़ा दरें घटा रहा है। यह प्रतिस्पर्धा एनएसआईसीटी की क्षमता के बिना संभव नहीं हुई होती।

- (x) पीएण्डओ पत्तनो ने पूर्व में यह विचार व्यक्त किया है कि उनसे ऐसी क्षमता के प्रोगे सस्थापित करने की क्षमता की गई है, जिनके ड्राफ्ट का प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप पूरा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एनएसआईसीटी के लिए यह अनुचित है अगर उन्हें ऐसे उपस्कर की पूंजीगत लागत का वहन करना पड़े। समान रूप से लाइनो और व्यापार जगत के लिए इस उपस्कर की लागत वहन करना अनुपयुक्त है अगर इसकी पूर्ण क्षमता वास्तव में वसूली योग्य नहीं है। एनएसआईसीटी के उपस्कर और विशेषकर प्रोगे के उपयोग को समझना अनुदेशात्मक है यह निश्चित होना चाहिए कि उपस्कर की राशि उत्पादन के अनुरूप है।
- (xi) एनएसआईसीटी की शेयरपूजी का 95% पीएण्डओ पत्तनो द्वारा धारित है जो तब स्वयं प्रमादी रूप से एनएसआईसीटी को 'तकनीकी सेवाएं' प्रदान करते हैं जिसके लिए वे शुल्क प्रभारित करते हैं। यह मोटे तौर पर एनएसआईसीटी से लिए गए लाभ को अधिकतम करने का एक कार्यवाही है। ऐसा कहते हुए यह अतर्कनीय है कि टर्मिनल को समस्त अपने विकास के प्रारम्भिक चरणों में अतिरिक्त प्रबन्धन विशेषज्ञता की अपेक्षा होगी और उसके बाद समय-समय पर कुछ विशेषज्ञों की सलाह अपेक्षित हो सकती है। तथापि, यह सुझाव देना कि ऐसी सेवाएं निरंतर अपेक्षित होती हैं और क्षतिपूर्ति के इन स्तरों पर यह अनुपयुक्त प्रतीत होती है। अपेक्षित सुझाव का स्तर कम हो जाएगा जब टर्मिनल परिपक्व होता है और जबकि लाइन परामर्शी बाजार के कार्यकरण से संबंधित नहीं है, फीस की संरचना विशेष प्रतीत होती है। यह स्पष्ट नहीं है यह अमरीकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर क्यों आधारित होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नियत और परिवर्तनीय घटक क्यों होंगे। अगर कोई टीएसएफ अदा किया जाना है तो वह प्रबन्धन समय अथवा कुछ अन्य अधिक सबद्ध उपाय पर आधारित होगा। प्रदान की गई सेवाओं की सूची पर बहस करने योग्य होने के लिए यह सहायक होगा, अधिकांश मदे परामर्शदाताओं के क्षेत्र की अपेक्षा कंपनी के उनके सामान्य दायित्वों के निर्दहन में उनके प्रबन्ध क्षेत्र में अधिक आना प्रतीत होती है।

V. मुम्बई और न्हावा शेवा जहाज एजेंट संघ

- (i) आय सदैव प्रवर्तकों द्वारा "निवेशित पूंजी" के रूप में मापी जाएगी। प्रशुल्क में किसी परियोजना के लिए "नियोजित पूंजी" पर आय शामिल नहीं करेगी, जिसे महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण और सरकार "दीर्घावधिक ऋणों" पर देय ब्याज से 6% अधिक प्रदान करती रही है।
- (ii) जहा पत्तन न्यासों के मामले में "नियोजित पूंजी" पर आय पर प्रशुल्क नियत करने के लिए विचार किया जाता है, जबकि निजी प्रचालकों के मामले में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रवर्तकों द्वारा 'निवेशित पूंजी' पर पर्याप्त आय सुनिश्चित करना चाहिए और अपनी सामान्य/मुक्त प्रारक्षित निधि भी शामिल करना चाहिए जिसकी परिभाषा "शेयरधारक निधि"/निवल संपत्ति के रूप में दी जाती है।
- (iii) सर्वसम्मति से निजी पत्तनो के मामले में प्रवर्तकों द्वारा निवेशित पूंजी पर आय और पत्तन न्यासों के मामले में नियोजित पूंजी पर आय पर विचार करते हुए प्रशुल्क नियत करने के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार है, क्योंकि पत्तन न्यासों और निजी पत्तनो के मामले में बुनियादी वित्तीय ढांचे में अंतर है। निजी प्रचालकों के लाभ को लाभश के रूप में वितरित किया जा सकता है, जबकि पत्तन न्यासों के मामले में ऐसा कोई वितरण नहीं है। चूंकि, "नियोजित पूंजी" पर आय की पत्तन न्यासों को अनुमति देना प्रश्न योग्य है, इसलिए इसे निजी पत्तन प्रचालकों को प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
- (iv) जबकि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) एनएसआईसीटी पर लागू किया गया है, यह इंगित नहीं किया गया है कि धारा 80-आईए के अधीन एनएसआईसीटी पर लागू 100% कर की कटौती पहले अनुमत्य 5 वर्ष की तुलना में 10 वर्षों तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार आयकर अधिनियम के अधीन प्रोत्साहनों के प्रावधानों के बारम्बार परिवर्तन से कर-पश्च लाभ की बजाय कर-पूर्व लाभ पर आय का विचार करना उचित है।
- (v) लाभश वितरण कर को लागू करने के पूर्व लाभश आय प्राप्तकर्ता पर कर योग्य था। ऐसे लाभश आय पर कर की सामान्य दर 35 से 40% हुई होती और यह पहले बहुत अधिक थी। वर्ष-1997 में उपरोक्त प्रावधान

लागू करके कंपनी से घोषित लामांश की राशि पर 10% कर अदा करने की अपेक्षा होती है और लामांश के प्राप्तकर्ता पर ऐसी लामांश आय पर कर नहीं लगाया जाता। इस प्रकार, एनएसआईसीटी को जहाँ घोषित लामांश पर कर अदा करना होगा, वहीं लामांश के प्राप्तकर्ता पर कर नहीं लगाया जाएगा।

8.1 इस मामले में संयुक्त सुनवाई "नियोजित पूँजी पर आय" के सीमित मुद्दे पर थी। परंतु, यहाँ तक कि अन्य मुद्दों पर भी विभिन्न पार्टियों द्वारा कई टिप्पणियाँ की गई हैं। इन्हें दर्ज कर लिया गया है और पृथक् रूप से विचारार्थ रखा गया है। चूंकि, जैसा पहले कहा गया है, वर्णित आशय सभी निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क मामलों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपलब्ध अवसर का उपयोग करना था न कि विचारार्थ एनएसआईसीटी के मामले के संदर्भ में ही।

8.2 यहाँ तक कि "नियोजित पूँजी पर आय" के सीमित मुद्दे पर यह मानना होगा कि दी गई टिप्पणियाँ किसी रिकार्ड के संदर्भ में स्पष्ट त्रुटि के संदर्भ में हैं। चूंकि, इस मामले के संबंध में संयुक्त सुनवाई "हमारी त्रुटि की समीक्षा" के अनुप्रयोग के बारे में थी। टिप्पणियाँ जो इस पृष्ठभूमि में सगत हैं, को प्रत्येक मुद्दे के अधीन दर्ज हमारे विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में माना गया है।

8.3 शेष टिप्पणियों को भी या तो मौजूदा मॉडल बनाए रखने अथवा नए मॉडल विकसित करने के लिए अलग से विचारार्थ रखा गया है।

8.4 आर्थर एंडरसन की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के साथ एनएसआईसीटी द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और निवेशों पर आय के सीमित मुद्दे पर संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों का विश्लेषण किया गया था। इस मामले पर कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र भूषणा के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है :-

I. तकनीकी सेवा शुल्क

प्राधिकरण का आदेश

- (i) कंटेनर टर्मिनल के विकास और प्रचालन की बीओटी सविदा अन्य बातों के साथ-साथ प्रवर्तकों की विशेषज्ञता और साख के आधार पर पीएण्डओ आर-इलिया के नेतृत्व वाले परिसंघ को दी गई है। एनएसआईसीटी रियायत करार में यथासंकल्पित परवर्ती सृजन था।
- (ii) तकनीकी सेवा शुल्क (टीएसएफ) का प्रदान की गई सेवा से कोई सबंध नहीं है। यह प्रवर्तक को देय लामांश की प्रकृति में अनिवार्यतः एक नियत भुगतान है। लाम की प्रतिशतता के रूप में परिवर्ती तकनीकी सेवा शुल्क का निर्धारण और करो को सकल रूप देने की पद्धति इस विचार का पुनर्बलन करती है।
- (iii) किसी भी महापत्तनों में समान स्थिति वाला निजी टर्मिनल प्रचालक मुख्य प्रवर्तक को तकनीकी सेवा शुल्क अदा करने की पद्धति का अनुपालन नहीं कर रहा है।
- (iv) बीओटी करार प्रवर्तक की विशेषज्ञता के आधार पर प्रदान किया गया है और प्रवर्तक से संबंधित रियायत करार के अधीन गठित भारतीय कंपनी को विशेषज्ञता देने की आशा की जाती है।
- (v) एफआईपीबी और आरबीआई द्वारा दी गई स्वीकृति को तकनीकी सेवा शुल्क को प्रत्यायोजित करने की अनुमति के रूप में देखा जा सकता है, जबकि ऐसे प्रत्यायोजन के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। वही इस भुगतान को प्रशुल्क निर्धारण के लिए लागत घटक के रूप में नहीं माना जा सकता।
- (vi) तकनीकी सेवा शुल्क का भुगतान निश्चित रूप से नियोजित पूँजी पर आय की प्रकृति में है और इसे आय के एक भाग के रूप में मानने की आवश्यकता है।

एनएसआईसीटी की टिप्पणिया

- (i) एफआईपीबी प्रेषण अनुमोदन निकाय नहीं है । यह उचित रूप से विचार करने के बाद ऐसे शुल्क का अनुमोदन करता है ; प्रसंगवश, एफआईपीबी में विभिन्न मंत्रालयों से सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं ।
- (ii) तकनीकी सेवा शुल्क लाभांश कार्यतन्त्र नहीं है । एनएसआईसीटी और पीएण्डआ पतन दो पृथक् विधायी संगठन हैं । किसी एक की सेवा दूसरे को मुफ्त उपलब्ध नहीं हो सकती ।
- (iii) अगर महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा उठाया गया कदम सही है तो वित्तीय निवेशक और उस निवेशक, जो प्रौद्योगिकी लागता है, के बीच कोई अंतर नहीं है ।
- (iv) किसी भी विधान (अर्थात् कंपनी अधिनियम) में ऐसे भुगतान का लाभांश अथवा पूँजी पर आय नहीं माना गया है ।
- (v) तकनीकी सेवा शुल्क को भारत सरकार का अनुमोदन है ।
- (vi) हमारे करार को अब संशोधित कर दिया गया है । अब कर के लिए तकनीकी सेवा शुल्क को जोड़ना आवश्यक नहीं है ।

मैसर्स आर्थर एडरसन की टिप्पणिया

- (i) भारत में अन्य दर विनियामक प्रणालिया विशेष रूप से तकनीकी सेवा शुल्क भुगतानों के व्यवहार पर ध्यान नहीं देती । यह अनुमान किया जा सकता है कि इन प्रणालियों में उचित कारोबारी व्यय की अनुमति देने के स्थूल सिद्धांत तकनीकी सेवा शुल्क के भुगतान पर लागू हो सकते हैं ।
- (ii) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तकनीकी सेवा शुल्क का भुगतान और ऐसे तकनीकी सेवा शुल्क के भुगतान पर लगाए गए कर का किसी भारतीय कंपनी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है । तथापि, आयकर प्राधिकारी व्यय के उस भाग जिसे वह ऐसी सेवाओं के बाजार मूल्य प्राप्त लाभ और कारोबार की सही आवश्यकता के सबंध में अधिक अथवा अनुचित समझ, पर कर की कटौती की अनुमति नहीं दे सकता।
- (iii) एफआईपीबी द्वारा अनुमोदन बातचीत पर आधारित और विभिन्न मुख्य कारणों के विस्तरेण के अधीन होते हैं। एफआईपीबी के साथ बातचीत कारोबार और वाणिज्यिक विवादों पर तथा साथ ही उन मामलों जो निवेशक और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभाव होती है के आधार पर होती है ।
- (iv) जहां तकनीकी सेवा शुल्क का भुगतान एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित तकनीकी सेवा करार के अधीन किया जाता है वहां यह असंभाव्य है कि आयकर प्राधिकारी इस आधार पर कटौती की अनुमति नहीं देंगे कि भुगतान अधिक अथवा अनुचित हैं । अगर आयकर प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी सेवा शुल्क की अनुमति दी जाती है तो उन्हें विनियामकों द्वारा उचित कारोबारी व्यय माना जा सकता है और उस लागत आधारित प्रशुल्क में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है ।

विवरण

मैसर्स आर्थर एडरसन का अन्य विनियमित क्षेत्रों में चूक द्वारा तकनीकी सेवा शुल्क के भुगतान की स्वीकार्यता के बारे में अवलोकन पूर्वानुमानिक और परिकल्पित है । रिपोर्ट से प्रभावी तौर पर सामन आन वाली स्थिति यह है कि अन्य विनियामकों में से किसी ने भी प्रशुल्क में लागत आग से जान के रूप में तकनीकी सेवा शुल्क के भुगतान को स्पष्टतया स्वीकार नहीं किया है ।

एकमात्र इसलिए, क्योंकि तकनीकी सेवा शुल्क को आयकर प्राधिकारियों द्वारा एक स्वीकार्य कारोबारी व्यय माना जाता है और इसे एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, इसलिए किसी विनियामक पर इसकी प्रसूत निर्धारण के लिए

लागत की एक मद के रूप में अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। इन प्रत्येक प्राधिकारियों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मुद्दों की सवीक्षा के लिए स्वयं अपने मानदंड बनाए हैं। यह सुविदित तथ्य है कि मूल्यहास निकालने की विधि कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के बीच भिन्न-भिन्न होती है। एनएसआईसीटी (जो एक पंजीकृत भारतीय कंपनी है) के मामले में इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क वृद्धि के निर्धारण के लिए कंपनी अधिनियम के मादंडों के अनुसार मूल्यहास की अनुमति दी है। इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को समान तरीके से मूल्यहास आकलित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को बाध्य करना नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, अन्य प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सदैव इस प्राधिकरण के लिए एकमात्र नियंत्रक कारक होना आवश्यक नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण ने तकनीकी सेवा शुल्क भुगतान को अनुचित अथवा तर्क विरुद्ध के रूप में घोषित नहीं किया था। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तकनीकी सेवा शुल्क भुगतान के प्रत्यायोजन की उपयुक्तता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया गया है। इस प्राधिकरण ने केवल अपने आदेश में दिए गए विस्तृत कारणों से प्रशुल्क निर्धारण के लिए इस भुगतान को लागत घटक के रूप में नहीं मानने का निर्णय लिया है। अगर एनएसआईसीटी इस प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे इस मुद्दे को किसी अन्य उपयुक्त मंच पर उठाना होगा। चूंकि रिकार्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, इसलिए जहां तक तकनीकी सेवा शुल्क के मुद्दे का संबंध है, हमारे आदेश की समीक्षा आवश्यक नहीं है।

प्रसंगवश, एनएसआईसीटी ने कहा है कि तकनीकी सेवा शुल्क को कर के लिए अब नहीं जोड़ा जाता। यह स्वागत योग्य परिवर्तन है। तथापि, इस मव में एनएसआईसीटी और पीएण्डओ पत्तनों के बीच करार का संशोधन इस लेन-देन की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता और इसलिए प्रशुल्क निर्धारण में इसका व्यवहार हुआ है।

II. न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर

प्राधिकरण का आदेश

- (i) लागत घटक के रूप में लाभांश वितरण कर पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह वस्तुतः शेयरधारकों की ओर से अदा किया गया/देय हिस्सा है और स्रोत पर कर की कटौती के समान है।
- (ii) कर की दरें आवधिक परिवर्तन के अधीन हैं, और कर के कारण व्यय कंपनी द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ का कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशुल्क निर्धारण के लिए पहले से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की देयता का अनुमान लगाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- (iii) निवल अधिशेष के अनुमान से कराधान के प्रभाव को निकालना उपयुक्त है। अगर यह नहीं किया जाता है तो इक्विटी पर कर-पूर्व अधिक लाभ निर्धारित करके पर्याप्त प्रतिपूर्ति की अनुमति देने की आवश्यकता हो सकती है।
- (iv) टीआरआई प्रशुल्क के निर्धारण के लिए प्रचालकों के लाभ पर कराधान के प्रभाव पर विचार नहीं करता।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) मूल्यनिर्धारण निर्णय लेते समय कर कंपनी के लिए लागत है। सभी कारोबार में प्रशुल्कों का नियतन करते समय कराधान के प्रभाव पर सदैव विचार किया जाता है।
- (ii) लाभांश वितरण कर न तो स्रोत पर काटा गया कर है और न ही शेयरधारकों की ओर से अदा किया गया कर। वितरण करने वाली कंपनी पर कर लगता है उसके शेयरधारकों पर नहीं।
- (iii) प्राधिकरण इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकता कि महापत्तन न्यास कर के भुगतान के अधीन नहीं है, परंतु एनएसआईसीटी कर अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

- (iv) टीआरआई करों की अनुमति नहीं देने का कोई संदर्भ नहीं दिया है । इस विषय से संबंधित उसके आदेश इन करों के अधिशेषण के पूर्व के हैं । 20% कर-पूर्व आय का अर्थ शेयरधारकों को प्रारक्षित निधियों में 10% अंतरण के बाद 15.08% कर-पश्चात् आय है ।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की टिप्पणियां

- (i) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लाभांश वितरण कर लाभांश वितरित करने वाली कंपनी के लिए कर लागत है, जिसके लिए भारत में जमा का दावा नहीं किया जा सकता । चूंकि, लाभांश का प्राप्तकर्ता लाभांश वितरण कर के लिए जमा का दावा करने का हकदार नहीं है, इसलिए यह प्राप्तकर्ता की ओर से कंपनी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की प्रकृति में नहीं है ।

विश्लेषण

यह मानना होगा कि शेयरधारक कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के लिए जमा प्राप्त नहीं करता। तथापि, वे प्राप्त लाभांश पर कोई कर अदा नहीं करते, जिसे वे डीडीटी लागू होने के पूर्व अदा कर रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में ही हमारे आवेश में यह उल्लेख किया गया है कि डीडीटी स्रोत पर कर की कटौती के समान है। टीडीएस होते हुए डीडीटी का भुगतान करने के बारे में कोई भ्रम नहीं है । केवल ऐसे भुगतान को शेयरधारक से कंपनी को कर लगाना अतिरिक्त करने के रूप में माना जाना होगा ।

यहां यह इंगित करना सगत है कि इस प्राधिकरण ने इक्विटी पर कर-पूर्व आय की अनुमति दी है, क्योंकि करो को प्रशुल्क में लागत निर्धारण नहीं माना जाता ।

एमएनएसए का करस्थान में बारम्बार परिवर्तन के बारे में अवलोकन सगत है और इस प्राधिकरण द्वारा माना जा चुका है । केवल इस पृष्ठभूमि में इक्विटी पर कर-पूर्व आय की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था ।

लाभांश वितरण कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की स्वीकार्यता के बारे में मुद्दा समीक्षा के लिए सगत बिंदु हो सकते हैं, परंतु इन मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 7 नवंबर, 2000 के आदेश में विचार किया जा चुका है । एनएसआईसीटी ने समीक्षा की आवश्यकता मांगते हुए रिकार्ड में स्पष्ट किसी भी त्रुटि को इंगित नहीं किया है । इसे ध्यान में रखते हुए, करों की स्वीकार्यता के संदर्भ में आदेश की समीक्षा आवश्यक नहीं है ।

III. विदेशी मुद्रा संबंधी मुद्दे

प्राधिकरण का आदेश

विदेशी मुद्रा दर की घट-बढ़ पर विचार करते हुए अशोषित विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित विदेशी मुद्रा की हानि पर एनएसआईसीटी का निवेश पर आय के लिए दावा सही नहीं कहा जा सकता । एनएसआईसीटी केवल वर्ष के दौरान वापसी-अदायगी योग्य विदेशी मुद्रा के संचय में विदेशी मुद्रा दर के घट-बढ़ के कारण हुई हानियों के लिए दावा कर सकता है ।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) विदेशी मुद्रा लेन-देन, जो पूंजीगत व्यय से संबंधित है, से उत्पन्न हुई वसूल नहीं की गई विदेशी मुद्रा हानियों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए और भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार संपदा की शेष उपयोगी अवधि में मूल्यहासित किया जाना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक वर्णन करता है कि वसूल नहीं की गई विदेशी मुद्रा हानियां लाभ और हानि लेखों में प्रसारित करना अपेक्षित है ।

- (ii) एनएसआईसीटी ने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक द्वारा यथानिर्धारित व्यवहार का अनुपालन किया है, क्योंकि यह स्थिति का ही चित्र प्रदर्शित करेगा ।
- (iii) प्राधिकरण द्वारा अनुपालन किए गए दृष्टिकोण के मामले में और एनएसआईसीटी की ऋण वापसी-अदायगी की पद्धति को देखते हुए बड़ी विनिमय हानियां उत्पन्न होगी और ऋण के 7वें वर्ष में उसका प्रभाव होगा, जिससे उस वर्ष में प्रशुल्क निर्धारण अवास्तविक हो जाएगा ।
- (iv) प्रशुल्क नियतन करने के लिए एनएसआईसीटी भारतीय लेखाकरण मानक में निर्धारित दृष्टिकोण अपनाने का इच्छुक है । प्राधिकरण अपने निर्णय पर दुबारा विचार कर सकता है और इस दृष्टिकोण को अनुमोदित कर सकता है ।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की टिप्पणियां

- (i) विदेशी मुद्रा लेन-देन और परिणामी विदेशी मुद्रा स्थिति के संबंध में भारतीय कंपनियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली लेखाकरण पद्धति इस्टीम्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक 11 (एएस-11) द्वारा निर्धारित की जाती है ।
- (ii) एएस-11 के अनुसार, जहां विदेशी मुद्रा ऋण का प्रयोग किसी अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ किया गया था, वहां ऋण के पुनः विवरण से उत्पन्न हुए अंतर को संबंधित अचल परिसंपत्ति की वहन राशि में समायोजित करना अपेक्षित है ।
- (iii) अन्य क्षेत्रों में विनियामक द्वारा विनिमय दर के अंतर को मानने का दो वैकल्पिक आधार प्रदान करता है —
 - (क) एएस-11 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में, और
 - (ख) ऋण की वापसी-अदायगी के समय ।
- (iv) एएस-11 का व्यवहार सगठन की स्थिति का अधिक यथार्थ चित्र प्रदान करेगा । एएस-11 का व्यवहार सगठन को ऋण के व्यवहार पर विनिमय दर भूल्यहास के प्रभाव को अलग करने योग्य बनाएगा ।
- (v) वापसी-अदायगी पर विनिमय दर में अंतर को मानने में संभावित रूप से किसी एक वर्ष में बड़ा वित्तीय प्रभाव हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लागत आधार प्रसारों (अगर विनियामक द्वारा अनुमत्य हो) में तीव्र वृद्धि अथवा सगठन द्वारा कारोबार संबंध लागत की गैर-वसूली (अगर विनियामक विनिमय हानियों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं देता) हो सकती है ।
- (vi) चूंकि, एएस-11 के अनुसार व्यवहार अचल परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि में विनिमय दर हानि का प्रभाव पर विस्तारित होगा, इसलिए यह दृष्टिकोण लागत आधार में तीव्र और समावित बारम्बार परिवर्तनों से ग्राहकों का बचाव करेगा ।

विश्लेषण

भारतीय कंपनी होने के कारण एनएसआईसीटी से इस्टीम्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है । तथापि, उन्होंने एएस-11 का अनुपालन नहीं किया है । अपने प्रशुल्क सशोधन संबंधी प्रस्ताव के साथ अनुमान प्रस्तुत करते समय एनएसआईसीटी ने भारतीय मानकों का अनुपालन नहीं किया और ऋण के पुनः विवरण के संपूर्ण अंतर को विदेशी मुद्रा घट-बढ़ के कारण हानियों के रूप में लाभ और हानि लेखों में प्रभावित किया है । तथापि, इस प्राधिकरण ने सगत वर्षों के दौरान अदा किए गए/वापसी-अदायगी योग्य ऋण की किस्त पर विदेशी मुद्रा घट-बढ़ के कारण हानि की अनुमति दी थी ।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की रिपोर्ट विशेष रूप से उल्लेख करती है कि अन्य क्षेत्रों में विनियामक द्वारा ऋण की वापसी-अदायगी के समय में भी विनिमय दर अंतर को मानने की व्यवस्था करता है ।

एनएसआईसीटी ने भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन नहीं किया, परंतु इसने अब प्राधिकरण से भारतीय लेखाकरण मानक अनुमोदित करने का अनुरोध किया है ताकि यह ऐसी विधि अपना सके । इस प्राधिकरण को लेखाकरण कार्यविधि पर एनएसआईसीटी को सुझाव देना आवश्यक नहीं है । उसे भारतीय कंपनियों के लिए स्वीकृत प्रणाली के आधार पर अपना लेखा रखना होगा । एनएसआईसीटी को भारतीय लेखाकरण मानक के अतिरिक्त किसी विधि द्वारा अपना अनुमान प्रस्तुत करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था । यहां तक कि इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मैसर्स आर्थर एडरसन द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों को देखते हुए गलत नहीं कहा जा सकता ।

अगर एनएसआईसीटी अपनी लेखाकरण कार्यविधि सशोधित करता है तो यह प्राधिकरण प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा ऋण के पुनः विवरण पर हानि के बारे में उस समय संभावित प्रयोग के लिए उपयुक्त रूप से विचार कर सकता है । चूंकि, यह भावी सशोधनों के लिए सगत है, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्राप्त अनुभव अथवा आदेश के बाद किए जाने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में समीक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए विदेशी मुद्रा हानि के मुद्दे के संदर्भ में हमारे आदेश की समीक्षा करने के लिए एनएसआईसीटी के तर्क में कोई योग्यता नहीं है ।

यहां तक कि यद्यपि, यह इस समीक्षा याचिका के प्रत्यक्षत संगत नहीं है, फिर भी सीएसएलए का प्रशुल्क के डोलरीकरण के बारे में अवलोकन पर उसकी प्राप्ति को हटाने के लिए यहा कार्यवाही करने की आवश्यकता है । यहां तक कि एनएसआईसीटी में उन डोलरीकृत प्रशुल्क मदों के संबंध में, भावी आय पूर्वानुमानों पर भारतीय रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर की अनुमानित वृद्धि को हिसाब में लेते हुए विचार किया गया है । अगर इस दृष्टिकोण का प्रयोग आय पूर्वानुमानों के लिए किया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसी सिद्धांत का प्रयोग व्यय का अनुमान लगाने में क्यों नहीं किया जा सकता । विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी-अदायगी से संबंधित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ में हानि के कारण निश्चित नकद प्रवाह है और इसे लागत अनुमानों में माना गया है । केवल इक्विटी के मामले में ऐसी विधि नहीं अपनाई जाती, क्योंकि इक्विटी पर आय की दर भारतीय पूंजी बाजार अनुमानों के संदर्भ में नियत की गई है । आय और व्यय के अनुमानों, दोनों में विदेशी मुद्रा घट-बढ़ के प्रभाव पर विचार करते हुए इसे प्रशुल्कों का "डोलरीकरण" नहीं कहा जा सकता ।

IV. नियोजित पूंजी पर आय

प्राधिकरण का आदेश

- (i) महापत्तनों और निजी टर्मिनलों प्रचालकों की पूंजी संरचना समान नहीं है ।
- (ii) बीओटी परियोजनाओं के संगत वैकल्पिक दृष्टिकोण के विकास का प्रहस्तन दीर्घावधिक संभावनाओं के साथ पृथक अध्ययन के भाग के रूप में किया जाना होगा । इसे ध्यान में रखते हुए एनएसआईसीटी के प्रस्ताव को निपटाने के लिए आवश्यक रूप से एक अतिरिम दृष्टिकोण अपनाना होगा ।
- (iii) अपनाया गया अतिरिम दृष्टिकोण एनएसआईसीटी के मामले में प्राप्त होने वाले 1:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात को स्वीकार करते हुए पूंजी के संबंधित स्रोतों की लागत की अनुमति देने के लिए है ।
- (iv) निवेश पर आय के रूप में अनुमत एनएसआईसीटी द्वारा प्राप्त निधियों के विभिन्न स्रोतों की लागत निम्नानुसार है :-
 - (क) ऋण: वर्ष के दौरान देय वास्तविक ब्याज,
 - (ख) तरजीही शेयर देय लाभांश की अपनाई गई दर अर्थात् 14% है ।
 - (ग) इक्विटी शेयर : टीआरआई प्रशुल्क निर्धारण के लिए इक्विटी की वापसी में 20% इक्विटी पर विचार कर रहा है । पूंजी की लागत के विषय पर विशेषज्ञों अर्थात् 'क्राइसिल', प्राइस वाटर हाऊस कूपर द्वारा किया गया अध्ययन भी इस आंकड़े को 20% के आसपास निर्धारित करता है । इसे ध्यान में रखते हुए, इक्विटी पर 20% की अनुमति दी जाती है ।
- (v) इक्विटी पर अनुमत आय एक कर-पूर्व आय है ।

एनएसआईसीटी की टिप्पणिया

- (i) एनएसआईसीटी के मामले में, प्राधिकरण ने महापत्तन न्यासों और अन्य निजी प्रचालकों के मामले में अनुपालन किए गए नियोजित पूंजी पर आय के दृष्टिकोण से विपणित होते हुए एक निम्न दृष्टिकोण अपनाया है। प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया अतिरिक्त आकार स्वेच्छाकारी है और एनएसआईसीटी के लिए हानिकारक है।
- (ii) प्राधिकरण ने इस मामले में स्वयं अपने परामर्शी दृष्टिकोण के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया है और इस प्रकार उसने निजी निवेशकों को अपने विचार देने का अवसर नहीं दिया है।
- (iii) निजी टर्मिनलों को पूंजी की लागत के आधार पर कर-पूर्व आय और नियोजित पूंजी के आधार पर पत्तन न्यासों को कर-पश्चात् आय की अनुमति देना अनुचित है और विभिन्न प्रचालकों को समान अवसर प्रदान करने के संपूर्ण उद्देश्य में योगदान नहीं करता।
- (iv) पूंजी की लागत पूंजी पर आय से निम्न है। पूंजी पर आय में पूंजी की लागत से अधिक अनुमानित लाभ का घटक शामिल होता है।
- (v) एनएसआईसीटी को 'क्राइसिल' और पीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए अध्ययनों से सबद्ध होने का लाभ नहीं मिला था। प्राधिकरण इन निष्कर्षों की एनएसआईसीटी के साथ भागीदारी कर सकता है।
- (vi) एनएसआईसीटी के ऋण की लागत कम है, क्योंकि इस ऋण की गारंटी पीएण्डओ, आस्ट्रेलिया लिमिटेड द्वारा की गई है। एनएसआईसीटी को किसी प्रकार के बिना इस ऋण की गारंटी देकर यह उचित है कि निवेशकों को आय के लिए पात्र होना चाहिए, जिसे प्राधिकरण द्वारा नकारा जा रहा है।
- (vii) प्रतिधारित अर्जन को रोयल्टी के रूप में निधि का घटक माना जाना चाहिए। इन अर्जनों का कारोबार में पुनः निवेश किया जाता है। ये प्रतिधारित अर्जन कारोबार की निवल संपत्ति के घटक हैं और आय के हकदार हैं।
- (viii) प्राधिकरण अपने अतिरिक्त दृष्टिकोण की समीक्षा कर सकता है और प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट, उद्देश्यपरक और वैश्विक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बनाए जाने तक एनएसआईसीटी को नियोजित पूंजी पर 20% की आय की अनुमति दी जा सकती है।

मैसर्स आर्थर एडरसन की टिप्पणिया

- (i) पूंजी पर उचित आय वह होगी जो निधियों की अवसर लागत और लिए गए व्यापारिक जोखिम से संबंधित हो। पूंजी पर आय की विनियामक दर इन विचारों तथा साथ ही क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता, सरकार के सामाजिक और विकासत्मक उद्देश्यों तथा अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- (ii) (क) विद्युत पारेषण और वितरण क्षेत्र में अचल परिसंपत्तियों के पूंजी आधार और नकदी तथा भंडार के मानकीय स्तर में से दीर्घावधिक ऋण और विशेष प्रारक्षित निधिया घटाकर 16% कर-पश्चात् आय की अनुमति दी जाती है।
- (ख) विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन परियोजना के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त इक्विटी और मुक्त प्रारक्षित निधि पर 16% कर-पश्चात् आय की अनुमति दी जाती है। विदेशी इक्विटी के मामले में, अभिदत्त पूंजी की मुद्रा में 16% आय की अनुमति दी जाती है।
- (ग) टीआरएआई नियोजित पूंजी पर 25-30% की आय की अनुमति देता है, जो निवल संपत्ति और निवल संपत्ति घटक तथा सबद्ध परिसंपत्तियों में ऋण निवेश का योग है।
- (घ) नियंत्रित थोक औषधि विनिर्माण क्षेत्र के मामले में विनिर्माता नियोजित पूंजी पर 22% कर-पूर्व आय अथवा निवल संपत्ति पर 14% कर-पश्चात् आय (निवल संपत्ति इक्विटी और मुक्त प्रारक्षित निधि में से बाह्य निवेश घटा कर योग है, नियोजित पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी पर योग है) लागू करने का चयन कर सकता है।

- (iii) विदेशी निवेशक साधारणतया अपने निवेश के मूल्य में अनुमानित मुद्रा मूल्यहास से संरक्षण के किसी रूप को अधिमानता देते हैं। इसे या तो उनकी इक्विटी के पुनः विवरण पर उत्पन्न होने वाली विदेशी इक्विटी को प्रदान करने के माध्यम से अथवा अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया विनिमय दर को विदेशी इक्विटी पर अनुमत्य आय के सूचकांकिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परवर्ती दृष्टिकोण की अनुमति विदेशी इक्विटी पूंजी के संबंध में विद्युत उत्पादक कंपनियों के मामले में दी गई है।
- (iv) साधारणतया, निवेशक आयकर विनियमों से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कर-पश्च आय अर्जित करने को अधिमानता देता है। आयकर दर में उर्ध्वमुखी संशोधन अथवा आय की अनुमत्य दर में समतुल्य परिवर्तन के समय नया कर लागू करना एक दर विनियमित उद्योग में किसी निवेशक की आय संबंधी अनुमान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विरलेक्षण

यह सत्य है कि यह प्राधिकरण महापत्तन न्यासों के मामले में अपनाए गए आरओसीई मॉडल से निजी टर्मिनल प्रचालकों के मामले में विधियों के संबंधित स्रोतों पर विशिष्ट मद मुक्त आय में परिवर्तित हो गया। यह विपथन हमारे आदेश के पैराग्राफ 9 (xiii) में वर्णित कारणों के लिए किया गया। अपनाई गई विधि स्वेच्छाचारी नहीं है, परंतु समग्र रूप से ध्यान दिए जाने और कारणों से है।

एनएसआईसीटी का यह तर्क कि उसके उधारों पर ब्याज की दर कम है, क्योंकि पीएण्डओ आस्ट्रेलिया ने एनएसआईसीटी पर किसी प्रकार के बिना ऋण की गारंटी दी है, संगत नहीं है। टर्मिनल के लिए पीएण्डओ आस्ट्रेलिया की बोली की संवीक्षा उसकी वित्तीय स्थिति पर आधारित थी। एनएसआईसीटी बाद में सृजित हुआ था। पीएण्डओ आस्ट्रेलिया से ऋण वित्त की व्यवस्था करने की आशा थी, और ऐसा कुछ विशेष उसने नहीं किया है, जिसकी उससे आशा नहीं थी।

प्रतिधारित अर्जन, जैसा मैसर्स आर्थर एंडरसन की रिपोर्ट में उल्लिखित है, पर अन्य क्षेत्रों में आय की अनुमति देने के लिए विचार किया गया है, अगर वे परियोजना की परिसंपत्तियों में निवेश किए जाते हैं। इस प्राधिकरण ने कभी भी यह निर्णय नहीं लिया है कि प्रतिधारित अर्जन आय के लिए अर्हक नहीं होगा। एनएसआईसीटी के मामले में यहां तक कि ऋण और इक्विटी पूंजी का परियोजना की परिसंपत्तियों में पूरी तरह निवेश नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिधारित अर्जन पर आय की अनुमति देने का भिन्नकूल प्रश्न नहीं उठता।

सरजीही शेयर पर आय की अनुमति स्वयं एनएसआईसीटी द्वारा अपनाई गई दर पर दी गई है।

इक्विटी शेयरों को 20% की कर-पूर्व आय की अनुमति दी गई है, जिसकी तुलना महापत्तन न्यासों के मामले में अनुमत्य 19.5% के आरओसीई (ऋणों पर ब्याज घटाकर) से भलीभांति की जा सकती है। इक्विटी पर उचित आय का हिसाब देश में शीर्ष वित्तीय परामर्शदाताओं द्वारा सूचित पूंजी बाजार अनुमानों के आधार पर लगाया गया है। एनएसआईसीटी के अपने परिकलनों के अनुसार अनुमत्य इक्विटी पर 20% कर-पूर्व आय लगभग 17% कर-पश्च आय होती है। मैसर्स आर्थर एंडरसन द्वारा सूचित अन्य क्षेत्रों में इक्विटी पर अनुमति योग्य आय से तुलना करने पर इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। मैसर्स आर्थर एंडरसन सूचित करता है कि टीआरएआई 30% कर-पूर्व आय की अनुमति देता है; उस अवसोकन की तथ्यात्मक यथार्थता निश्चित नहीं है। टीआरएआई ने हमें इंगित किया है कि यह इक्विटी पर केवल 20% की आय की अनुमति देता है, वह भी एक उद्योग-विशिष्ट आंकलन है न कि निवेशक-विशिष्ट आंकलन। टीआरएआई पूंजी निवेश पर 22% से 24% की दर पर वार्षिक आवर्ती व्यय की अनुमति देता है। इसमें मूल्यहास के लिए 10% का प्राक्कान शामिल है। यह मानना होगा कि एनएसआईसीटी के मामले में मूल्यहास की अनुमति लागत की एक पृथक भव के रूप में दी गई है और इससे अधिक इक्विटी पर 20% की आय मानी गई है।

एनएसआईसीटी का विदेशी निवेशकों से इक्विटी अंशदान और उन्हें लगभग 9% (करावकाश सहित) की आय की अनुमति देते हुए भारतीय रुपए के मूल्यहास के बारे में तर्क असंगत है। यह मानना होगा कि 20% कर-पूर्व आय रुपया निवेश

पर भारतीय पूंजी बाजार के अनुमानों के संदर्भ में नियत की गई है। यह उल्लेख करना व्यर्थ है कि अगर मुद्रा आधार परिवर्तित किया जाता है तो आय की दर को भी समायोजित करना होगा। विकास के इस चरण पर अमरीकी डॉलर की इक्विटी पर 20% की आय का अनुमान करना अतिआश्चर्यास्पद हो सकती है। हम निश्चित नहीं हैं कि क्या (यहां तक कि) अमरीकी पूंजी बाजार आधारभूत संरचना परियोजनाओं में आय का ऐसा स्तर प्रदान करता है या नहीं।

समीक्षा के लिए ऋण : इक्विटी अनुपात का मुद्दा बिल्कल संगत नहीं है। एनएसआईसीटी में प्राप्त हो रही स्थिति को लेते हुए 1:1 के अनुपात की अनुमति दी गई है। यह सत्य है कि अनुपात ऋण के आधिकारिक शोधन के साथ धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न होगा। यह मानना होगा कि ऐसे ऋण शोधन के लिए नकद प्रवाह मुख्यतः प्रशुल्कों से है। इसका अर्थ यह है कि प्रयोक्ता ऋणों की वापसी-अदायगी में भी अंशदान कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मात्र यह तथ्य कि ऋण का शोधन किया गया है, जहां तक आय की अनुमति देने का संबंध है, यह स्थिति परिवर्तित नहीं कर सकता। यह भी मानना होगा कि पूंजी मिश्रण का विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए बिना पूंजी के स्रोत के आधार पर निवेश पर आय की अनुमति देना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। जबकि निजी टर्मिनल का अपनी इच्छा का पूंजी मिश्रण हो सकता है, वहीं इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड को निवेशों पर आय की अनुमति देने के लिए ही माना जाएगा।

यह पुनः मानना होगा कि अपनाए गए निवेश पर आय संबंधी दृष्टिकोण पर एनएसआईसीटी को अपना विचार रखने का अवसर नहीं दिया गया था। परंतु, इस मूल का सुधार एमबीपीटी में दिनांक 3 सितम्बर, 2001 को आयोजित की गई संयुक्त सुनवाई में किया गया है। इस अवसर का उपयोग आगे शोधित मॉडल विकसित करने के लिए अन्य संबंधित संगठनों से परामर्श करने के लिए किया गया था। जहां तक समीक्षा का संबंध है, निम्नलिखित दो मुद्दे संगत हैं :—

(i) क्या आय की अनुमति देने के लिए निजी टर्मिनलों और महापत्तन न्यास के बीच किया गया भेद उचित है या नहीं।

(ii) क्या इक्विटी पर अनुमत कर-पूर्व आय उचित है या नहीं।

एनएसआईसीटी के मामले में इक्विटी पर अनुमत आय के औचित्य के बारे में मुद्दे पर विस्तारपूर्वक पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा की जा चुकी है। भारतीय बाजार दशाओं पर विचार करते हुए अनुमत आय को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

निजी टर्मिनलों और पत्तन न्यासों की पूंजी संरचना की तुलना नहीं होती है। पुराने पत्तन न्यास अभी भी अधिग्रहण के समय मूल्यांकन के आधार पर ऐतिहासिक लागत पर परिसंपत्ति मूल्यांकन (विशेषकर भूमि) की सूचना देते हैं। उनकी संरचना में कोई इक्विटी घटक नहीं है। वे सामान्य वितरित नहीं करते, परंतु प्रतिधारित अधिशेष का उपयोग भावी विकास के लिए किया जाता है। उन्हें सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए परिसंपत्तियां भी सृजित करनी होती हैं। जबकि महापत्तन ऋणों और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से परिसंपत्तियां वित्तपोषित करते हैं, वहीं निजी टर्मिनल ऋण और इक्विटी के माध्यम से निधियां जुटाते हैं। निजी प्रचालकों के मामले में पूंजी के विभिन्न स्रोतों की लागत सरलतापूर्वक पता लगाने योग्य होती है।

इन मतभेदों के बावजूद इस प्राधिकरण द्वारा पत्तन न्यासों के लिए नियोजित पूंजी पर आय की अनुमति देने की वर्तमान विधि की समीक्षा करने का निर्णय लिया जा चुका है। जैसा सीएसएलए द्वारा इंगित किया गया है, ऐसी विधि, जिसके अनिवार्यतः संशोधन की अपेक्षा है, को निजी टर्मिनलों को प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से पीएसए सिकाल (एसआईसीएल) और एबीजी जैसे निजी टर्मिनल प्रचालकों ने नियोजित पूंजी पर आय का मॉडल उन पर लागू करने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने केवल एनएसआईसीटी के मामले में अनुपालन किए गए मॉडल में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। पूंजी संरचना में विभेद के दृष्टिकोण निजी टर्मिनलों और महापत्तन न्यासों के मामले में आय की अनुमति देने के भिन्न मॉडलों का औचित्य है। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, महापत्तन न्यासों के लिए मौजूदा मॉडल की समीक्षा से संबंधित मामले पर अलग से कार्यवाई चल रही है।

सीएसएलए और एमएनएसए द्वारा दी गई टिप्पणियां इस प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विधि में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं देती।

इस मुद्दे पर पुनः रिकार्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। एनएसआईसीटी ने पत्तन न्यासों के मामले में अपनाई गई विधि से विपथित होते हुए निजी टर्मिनलों के मामले में इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ही चुनौती दी है। ऐसे विपथन के कारणों का वर्णन इस प्राधिकरण के दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के आदेश में किया जा चुका है। अगर एनएसआईसीटी अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता तो उसे अन्य मंच से इसके उपचार की मांग करनी होगी। इन कारणों से इस प्राधिकरण के लिए इस संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण के संदर्भ में अपने आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

V. क्षमता समुपयोजन और इविटटी पर आय

प्राधिकरण का आदेश

- (i) यहां तक कि यद्यपि एनएसआईसीटी ने 6.5 मिलियन टीईयू (रियायत करार में यथासंस्कल्पित) की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पूरी पूंजी लगा दी है, वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए औसत क्षमता समुपयोजन लगभग 82% है।
- (ii) न केवल पत्तन परियोजनाओं बल्कि किसी भी परियोजना में निवेश के संबंध में, निवेशक उचित रूप से प्रारंभ से ही अधिकतम पर आय प्राप्त करने का अनुमान नहीं करते।
- (iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान टर्मिनल के औसत क्षमता समुपयोजन पर विचार करते हुए तरजीही और इविटटी शेयरो पर अधिकतम 80% की आय की ही अनुमति दी जाती है।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) एनएसआईसीटी ने प्रतिवर्ष 800000 टीईयू के यातायात की गारंटी दी है, जिसे रियायत अवधि के 15वें वर्ष (रियायत करार का परिशिष्ट X) में प्राप्त करने का अनुमान है।
- (ii) क्षमता समुपयोजन के लिए आय पर प्रतिबद्ध लगाने के प्राधिकरण के निर्णय को स्वीकार करते हुए एनएसआईसीटी 6.5 मिलियन टीईयू के आंकड़े को संशोधित करके प्रतिवर्ष 80 लाख टीईयू करने का अनुरोध करता है। इस आंकड़े के आधार पर औसत क्षमता समुपयोजन 89.43% होगा।
- (iii) प्राधिकरण को पुरस्कार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जब अपेक्षित निवेश से अधिक अतिरिक्त निवेश से अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होती है।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की टिप्पणियां

- (i) क्षमता समुपयोजन कई मांग और आपूर्ति कारकों का कार्य है और कुछ कारक कभी-कभी विनियमित संगठन के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
- (ii) दूरसंचार क्षेत्र में, टीआरएआई ने बुनियादी और सेलूलर सेवा प्रदायकों को प्रथम दृष्टया अनुमानित नेटवर्क क्षमता समुपयोजन पर आय को संबद्ध किए बिना पूंजीनिवेश पर आय की अनुमति दी है। इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण संगठनों को क्षमता समुपयोजन के संदर्भ के बिना आय की अनुमति दी जाती है।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षेत्र में, जहां प्रमारों की वसूली क्षमता से संबद्ध है, वहीं निम्नलिखित आधार अपनाया गया है:-
 - (क) नियतन प्रमारों की पूर्ण वसूली के लिए आधार स्तर प्रशुल्क अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया और विद्युत क्रय करार में प्रतिबद्ध किया गया है।
 - (ख) आधार स्तर से अधिक उपलब्धता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
 - (ग) संगठन का उसके नियंत्रण से बाहर की कतिपय घटनाओं से उत्पन्न घोषित उपलब्धता को नहीं लेने से संरक्षण किया जाता है।

विश्लेषण

मैसर्स आर्थर एंडरसन की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ क्षमता के साथ निवेश पर अनुमति योग्य आय को संबद्ध करना विद्युत क्षेत्र में जहां प्रशुल्क अपेक्षित है, में मौजूद है। यहां तक कि एनएसआईसीटी ने स्वयं प्रयुक्त क्षमता से आय को संबद्ध करने का सिद्धांत स्वीकार किया है।

यहां तक कि यद्यपि हमारे परिकलनों में केवल 8.5 लाख टीईयू की क्षमता पर विचार किया गया है, टंकण की वृद्धि के कारण इसका हमारे आदेश में उल्लेख 8.5 मिलियन टीईयू कर दिया गया है। तथापि, टंकण की यह वृद्धि प्रशुल्क वृद्धि के परिकलन को प्रभावित नहीं करती। फिर भी इस वृद्धि को सुधारा जाना होगा।

यहां तक कि यद्यपि, रियायत करार के अनुसार गारंटीशुदा उत्पादन 6,00,000 टीईयू है, फिर भी एनएसआईसीटी ने अपने 3 अगस्त, 2000 के पत्र में कतिपय अतिरिक्त उपस्करों को जोड़े जाने के बाद 8.5 लाख टीईयू की क्षमता इंगित किया है। एनएसआईसीटी द्वारा दिए गए 30 वर्षीय पूर्वानुमान वर्ष 2000-2003 के लिए 6.5 लाख टीईयू का उत्पादन इंगित करते हैं, जो बढ़कर वर्ष 2005-2008 में 8.5 लाख टीईयू हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, विचार किए गए क्षमता समुपयोजन की प्रतिशतता संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, अगर वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए पूर्वानुमानित पूंजी ब्लॉक में वृद्धि 8.5 लाख टीईयू की क्षमता निर्मित करने के लिए अतिरिक्त उपस्कर के अधिग्रहण के कारण है तो हमारे आदेश में पहले विचार किए गए क्षमता समुपयोजन की प्रतिशतता कम की जानी होगी।

यहां उल्लेख करना संगत है कि अगर एनएसआईसीटी सीए के अधीन संकल्पित क्षमता पर रहना चाहता है तो प्रशुल्क के प्रयोजनों के लिए विचार किए जाने वाले पूंजी निवेश को भी उसके अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं से संबद्ध करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि एनएसआईसीटी ने सीए में दिए गए की अपेक्षा अधिक संख्या में उपस्कर जोड़े हैं और अतिरिक्त सुविधाएँ सृजित की है। यह भारी भूल कहे जाने वाले स्तर की बेमेलता होगी अगर किए गए वास्तविक निवेश पर सीए में संकल्पित क्षमता के न्यूनतम स्तर के साथ विचार किया जाता है।

VI. अधिक नकदी की कटौतीप्राधिकरण का आदेश

- (i) एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत अनुमान वर्ष 2000-2001 के दौरान अत्यधिक नकद और बैंक शेष दर्शाते हैं। यह शेष प्रारक्षित निधियों से बहुत अधिक है।
- (ii) चूंकि अधिक नकद धारिता निष्क्रिय पूंजी प्रदर्शित करती है, इसलिए प्रारक्षित निधि के आधिक्य में नकद शेष को तरजीही और इक्विटी शेयर पर आय को मानते समय निकाल दिया जाता है।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) प्राधिकरण ने अनुमोदित घटे हुए प्रशुल्क स्तर, भुगतान किए गए कर और लाम्बांश के प्रभाव पर विचार किए बिना 30% प्रशुल्क वृद्धि के लिए एनएसआईसीटी के आवेदन के आधार पर अधिक नकद की कटौती की है।
- (ii) नकद शेष का हिसाब अनुमोदित 16% वृद्धि के आधार पर दुबारा निकाला जाना चाहिए और तब शेयरधारकों पर करों और लाम्बांश के भुगतान के प्रभाव पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (iii) वर्ष के अंत में नकद शेष पर विचार करना सही स्थिति का वास्तविक प्रदर्शन नहीं है, बेहतर पद्धति समतुल्यकरण सुनिश्चित करने के लिए नकद के अथशेष और इतिशेष के एक औसत को अपनाना होगा।
- (iv) नकद शेष बैंकों में सावधि जमाओं के साथ अधिकतम प्रवाह पर 8% से अधिक की आय अर्जित नहीं करता। एनएसआईसीटी सुझाव देता है कि नकद शेष पर 10% पर ब्याज अर्जन औसत नकद शेष के 65% को प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाए, जो नकद पर पर्याप्त आय प्रदर्शित करेगा।

विश्लेषण

चूंकि, ऋण और इक्विटी के वर्षान्त शेष पर आय की अनुमति देने के लिए विचार किया गया है, इसलिए वर्षान्त अप्रयुक्त नकद शेष की कटौती सही है। दीर्घावधि में, औसत शेष अथवा वर्षान्त शेष पर विचार करने से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। प्रसंगवश, कार्यशील पूंजी सहित नियोजित पूंजी के इतिशेष पर महापत्तन न्यासों के मामले में भी विचार किया गया है।

कटौती किए गए अप्रयुक्त नकद शेष की राशि वास्तव में 30 वर्षीय पूर्वानुमान में एनएसआईसीटी द्वारा दिए गए प्रदर्शन पर आधारित है, जो प्रशुल्क आवेदन के अनुसार प्रशुल्क में 30% की वृद्धि का अनुमान करता है। यह अनुमत्य 18% की वृद्धि से कम हो सकता है। तथापि, यह अनुमत्य प्रशुल्क में वृद्धि को वस्तुतः प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि अनुमत्य संशोधन की प्रतिशतता लागत विवरण द्वारा प्रकटित वास्तविक घाटे से अधिक है। इसके अतिरिक्त, अधिक नकद शेष में कमी करना केवल एनएसआईसीटी के मामले में इस प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई कोई नई पद्धति नहीं है। कार्यशील पूंजी के आंकड़े को कई महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क संशोधन के मामले में उचित स्तर तक संयत किया गया है।

नकद शेष आदि पर 8% ब्याज की अनुमति देने के लिए एनएसआईसीटी द्वारा उठाया गया मुद्दा संगत नहीं है। यह मानना होगा कि एनएसआईसीटी के मामले में इस प्राधिकरण ने नियोजित पूंजी (नियत परिसंपत्ति + कार्यशील पूंजी) पर आय का निर्धारण करने की पारम्परिक विधि नहीं अपनाई है। एनएसआईसीटी को अनुमत्य आय निधि के स्रोतों के संदर्भ में भी, और इस परिप्रेक्ष्य में अधिक नकद प्रवर्धित निधियों का प्रचालन में निवेश नहीं किया गया और इसलिए इसकी कटौती की गई थी। यह दृष्टिकोण केवल प्रशुल्क निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ही अपनाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्राधिकरण ने एनएसआईसीटी के तुलन पत्र प्रबंधन की योग्यता को नहीं माना है।

VII. 30 वर्षीय अवधि का विश्लेषणप्राधिकरण का आदेश

- (i) प्रशुल्क को स्थिर रखते हुए किया गया 30 वर्षीय विश्लेषण उपयुक्त नहीं है।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) आदेश में यथाउल्लिखित परिकलन प्राधिकरण द्वारा सही देखा गया केवल सैद्धांतिक है और परिकल्पनात्मक है।
 (ii) प्राधिकरण को पूर्वानुमान के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आवेदन की समीक्षा करनी चाहिए। 30 वर्षीय अवधि के लिए अनुमान वास्तव में मूल्यनिर्धारण निर्णय में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। मांग और आपूर्ति के अतिरिक्त ये निर्णय वृहद-आर्थिक कारकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

विश्लेषण

एनएसआईसीटी के मामले में अनुमत्य प्रशुल्क वृद्धि उस समय विचार किए गए अनुवर्ती दो वर्षों के पूर्वानुमानों पर आधारित है। 30 वर्षीय विश्लेषण निर्णय लेने की प्रक्रिया को दी गई एक सहायता है, क्योंकि यह कुछ अर्थपूर्ण संकेतक (उदाहरणार्थ, इस मामले में टर्मिनल की क्षमता) प्रदान कर सकती है। इस संबंध में एनएसआईसीटी का अवलोकन सामान्य प्रकृति का है और इसके लिए हमारे आवेश की समीक्षा करना आवश्यक नहीं है।

VIII. भावी प्रशुल्क में समायोजनप्राधिकरण का आदेश

एनएसआईसीटी द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क और आय संबंधी पूर्वानुमान पर किसी संशोधन के बिना विश्वास किया गया है। अगर इस दृष्टिकोण से टर्मिनल प्रचालक को प्रशुल्कों के आगामी संशोधन के दौरान समीक्षा के समय कोई अनुचित लाभ दिया जाना प्रतीत होता है तो टर्मिनल प्रचालक को प्राप्त अनुचित लाभ प्रशुल्क के भावी संशोधन के एवज में समंजित किया जाएगा।

एनएसआईसीटी की टिप्पणियां

प्राधिकरण को यह सिद्धांत भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिकूल परिवर्तन, जो एनएसआईसीटी के वित्तीय स्थायित्व और आय को प्रभावित करते हैं, पर भी विचार किया जाएगा।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की टिप्पणियां

- (i) चूंकि लागत आधारित प्रशुल्क लागत के अनुमानों से विकसित होते हैं, इसलिए दी गई निविदियों की वास्तविक लागत में परिवर्तन विनियमित संगठनों और संपूर्ण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- (ii) कुछ क्षेत्रों जैसे विद्युत में प्रणाली में या तो सूचकांकीकरण कार्यतंत्र अथवा भावी प्रशुल्क संशोधनों के माध्यम से पहले पूर्वानुमानित स्तर की तुलना में ईंधन की लागत में उचित वृद्धि के लिए संगठनों की प्रतिपूर्ति करने का कार्यतंत्र है।

विश्लेषण

अगर कोई भी आयोजना परिसर में प्रचालक द्वारा किए गए अनुमान में संदर्भ में प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो उसके पास सदैव समय-अनुसूची से पूर्व प्रशुल्क समायोजन मांगने का विकल्प होता है। प्रसंगवश, एनएसआईसीटी के प्रशुल्क में नवंबर, 2000 का संशोधन समय-अनुसूची से पूर्व का संशोधन था, जिसकी अनुमति जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वरों के मान से अपनाए गए वरों को जारी रखने की बजाए एनएसआईसीटी के स्वयं अपने प्रचालन की लागत के संवर्ध में अपना प्रशुल्क रखने के अनुरोध के आधार पर दी गई थी।

अगर अनुमानों में भिन्नताएं प्रचालक के अनुकूल हैं तो यह संभावना है कि वह ऐसी भिन्नताओं के कारण उसे प्राप्त लाभ के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित प्रशुल्क की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं करे। इसी पृष्ठभूमि में ऐसे लाभों को भावी प्राप्तियों के एवज में समंजित करने के बारे में संवर्ध बिया गया था।

किसी भी तरह यह मुद्दा नवंबर, 2000 में अनुमत्य प्रशुल्क वृद्धि को प्रभावित नहीं करता। इसे ध्यान में रखते हुए आदेश की समीक्षा करना सगत नहीं है।

IX. विभिन्न प्रचालकों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के समरूप आधार का प्रयोगएनएसआईसीटी की टिप्पणियां

- (i) प्राधिकरण ने सदैव वर्णन किया है कि प्रशुल्क नियतन के लिए उसका दृष्टिकोण एक परामर्शी प्रक्रिया होगी। एनएसआईसीटी इस मामले में इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, परंतु यह अनुरोध करता है कि जब प्राधिकरण स्थापित व्यवहार से विपक्षित होता है तब उसे अभ्यावेदन करने का समान अवसर बिया जाए।
- (ii) इस विरोधी आदेश में, प्राधिकरण ने वित्तीय पैरामीटरों का एक संपूर्ण नया सेट कार्यान्वित किया है, जिस पर एनएसआईसीटी से उसके अभ्यावेदन के लिए नहीं कहा गया। प्राधिकरण ने स्कीम (ईएलटी) भी कार्यान्वित की है, जिस पर एनएसआईसीटी से उसके विचार नहीं मागे गए थे।
- (iii) प्राधिकरण को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो व्यावहारिक हो। ऐसे दृष्टिकोण को वास्तविकताओं और उद्योग में विद्यमान पद्धतियों पर भी विचार करना चाहिए। आज तक महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने साधारणतया महापत्तनों के मामले में स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन किया है, परंतु एनएसआईसीटी को डॉलर प्रशुल्क के लाभ नकार देने और आगे एक ईएलटी स्कीम जो रियायत करार की आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत अधिक सख्त है, को अधिरोपित करने और एनएसआईसीटी के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए वित्तीय मानदंड जो वैश्विक रूप से प्रयुक्त नहीं किए जाने वाले मानदंड हैं, अपनाने का भी चयन किया है।

मैसर्स आर्थर एंडरसन की टिप्पणियां

- (i) साधारणतया, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने सभी प्रचालकों/पत्तन न्यासों के लिए मानदंडों के एक समरूप सेट का प्रयोग किया है।

- (ii) तथापि, कुछ उदाहरणों में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा प्रथम दृष्टया एनएसआईसीटी की तुलना में अन्य पत्तनों/प्रचालकों के लिए लागत आधार प्रमारों के निर्धारण में भिन्न आधार अपनाना प्रतीत होता है। यह भिन्नता निम्न से संबद्ध है :-
- (क) एनएसआईसीटी के लिए चुकता पूंजी पर आय के विरुद्ध अन्य प्रचालकों को नियोजित पूंजी पर आय की अनुमति देना।
- (ख) अनुमानित क्षमता समुपयोजन की सीमा तक पूंजी पर एनएसआईसीटी की आय कम करना।
- (ग) प्रति घंटे चालन के रूप में प्रशुल्क से एनएसआईसीटी के प्रमारों को जोड़ना।
- इन भिन्नताओं का लागत आधार प्रमार के विकास के लिए एनएसआईसीटी के लागत आधार/अनुमत आय को कम करने पर प्रभाव होगा।

विश्लेषण

मैसर्स आर्थर एंडरसन द्वारा उल्लिखित तीन मुद्दों में से ईएलटी स्कीम से संबंधित मुद्दे ने अब अपनी संगतता खो दी है, क्योंकि यह प्राधिकरण अपने दिनांक 7 नवंबर, 2000 के आदेश द्वारा लागू ईएलटी स्कीम को रद्द कर चुका है। अन्य मुद्दों पर संबंधित शीर्षों के अधीन दिए गए विश्लेषण में विचार किया गया है।

9. ऊपर दिए गए विश्लेषण को देखते हुए हमारे दिनांक 7 नवंबर, 2000 के आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता के लिए रिकार्ड पर स्पष्ट कोई त्रुटि नहीं है। जैसा उल्लेख किया जा चुका है, एनएसआईसीटी द्वारा उठाए गए मुद्दे निजी टर्मिनलों के मामले में प्रशुल्क निर्धारण के प्रति पूर्णतः नए दृष्टिकोण के समर्थन में हैं। यह बिल्कुल एक भिन्न मामला है। एनएसआईसीटी के मामले में इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में उठाए गए बिंदुओं के संदर्भ में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर एनएसआईसीटी इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायतें दूर करने के लिए किसी अन्य उपयुक्त मंच से अनुरोध करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण एनएसआईसीटी के मामले में उसके द्वारा निर्धारित किए जा चुके दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधित करना आवश्यक नहीं पाता।

10. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र रूप से ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण अपने प्रशुल्क के संशोधन से संबंधित एनएसआईसीटी द्वारा इस प्राधिकरण के दिनांक 7 नवंबर, 2000 के आदेश की समीक्षा करने के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकृत करता है।

11. इस मामले में दिनांक 7 नवंबर, 2000 के पूर्व आदेश की समीक्षा नहीं करने का निर्णय होते हुए भी यह प्राधिकरण फिर भी इस कार्यवाही से उत्पन्न हुए कुछ मुद्दों पर समाहित प्रयोग के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण को परिशोधित करने के लिए आगे ध्यान देने की आवश्यकता मानता है। हमारे देश में पत्तन क्षेत्र इस अर्थ में परिवर्तन से गुजर रहा है कि निजी टर्मिनल बड़े पैमाने पर उभरना प्रारंभ हो गए हैं। उत्पन्न हो रही आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नए मॉडल विकसित किए जाने होंगे। परिवर्तन की किसी स्थिति में इसे कुछ समय के लिए अनवरत कार्य होना होगा; तत्काल अपनाने के लिए तुरंत उपलब्ध हल का अनुमान करना उचित नहीं होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/143/असाधारण-2001]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2001

No. TAMP/27/2001-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of an application submitted by the NSICT for a review of this Authority's Order dated 7 November, 2000 on revision of its Scale of Rates relating to container handling charges as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**Case No. TAMP/27/2001-JNPT****Nhava Sheva International Container
Terminal Limited (NSICT)**

- - -

Applicant**ORDER**

(Passed on this 20th day of September 2001)

This Authority passed an Order on 7 November 2000 disposing of the proposal of the Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT) for revision of its Scale of Rates relating to container handling charges.

2. NSICT has now submitted an application for a review of the Order on the following main issues:

- (i). Allowability of Technical Service Fees.
- (ii). Inclusion of tax as a cost element for determining tariff.
- (iii). Return on capital employed
- (iv). Basis of allowing foreign exchange losses.
- (v). Application of uniform basis of tariff for different operators.

3.1. The NSICT has stated that it had commissioned M/s. Arthur Andersen to study the pertinent issues and advise it. The NSICT has also forwarded a copy of the report submitted to it by M/s. Arthur Andersen. Initially, the NSICT had requested to maintain confidentiality of the report submitted by M/s. Arthur Andersen and not to circulate this report without written consent of the NSICT and M/s. Arthur Andersen.

3.2. Since the NSICT had requested to maintain confidentiality of the Arthur Andersen Report, it was informed that the Report would be taken into consideration only if the stipulation about maintaining confidentiality was withdrawn. This has become necessary since the analysis of the NSICT application in this case has to essentially deal with the views expressed in that Report if it is taken on record for consideration. The NSICT has subsequently informed that it withdraws the confidentiality condition attached to that Report.

4. This petition has been registered as a 'review' case. The issues presented for reconsideration are related to the approach adopted by the Authority in determining the tariff increase. Since no new issues have been raised, the review application was not forwarded to the concerned users for comments.

5.1. On a preliminary consideration of the matter, this Authority decided that it would not be necessary to provide an opportunity for the NSICT to set up a Presentation by M/s. Arthur Andersen of their analysis of the impugned Order. The averment of the NSICT that an opportunity of hearing was not given to the Private Terminals to offer their views before adopting a new approach to Return on Investment in their cases was, however, considered in particular. It was decided that the procedural lapse pointed out by the NSICT might be rectified by setting up a joint hearing on the limited issue of Return on Investment whereafter the case could be finally disposed of duly taking into account the arguments advanced in the proposed hearing. It was also decided that the opportunity available would be utilised for developing a common approach to tariff cases of all Private Terminals and not just with reference to the NSICT case under consideration.

5.2. Pursuant to the decisions mentioned above, a joint hearing was fixed in the matter relating to Return on Investment allowed to Private Terminals at the MBPT premises on 3 September 2001. Apart from the NSICT, the following organisations/representative bodies of port users and trade were also invited to participate in the hearing:

- (1). PSA SICAL Terminal Limited.
- (2). Chennai Container Terminals Limited.
- (3). Jawaharlal Nehru Port Trust.

- (4). Tuticorin Port Trust.
- (5). Mormugao Port Trust.
- (6). Chennai Port Trust.
- (7). ABG Heavy Industries Ltd.
- (8). Indian National Shipowners' Association.
- (9). Container Shipping Lines Association.
- (10). Federation of Freight Forwarders' Association in India.
- (11). Federation of Association of Stevedores.
- (12). Confederation of Indian Industry.
- (13). Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry.
- (14). Indian Merchant Chamber.

6 At the joint hearing, the following submissions were made:

The Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT
(also representing the Chennai Container Terminal Limited.)

- (i). The BOT agreements have stringent requirements which a Private Operator must meet.
- (ii). Please go by the Return on Capital Employed method instead of adopting Cost of different Sources of Capital.
- (iii). Pre-tax Return is not adequate if tax liability is to be absorbed.
- (iv). Our Parent Company has guaranteed loans by absorbing the risks. It has not passed on the risk to the NSICT. The Return on Equity shall, therefore, be more.
- (v). Debt enjoys tax benefits. Equity does not. Please consider the differentiation.
- (vi). Foreign Exchange losses have not been considered.
- (vii). How will we get a return of 20% on unutilised capital elsewhere?
- (viii). The CSLA'S observations about post-Panamax Cranes are not consistent with what they say to us. The INPT is planning to deepen the channel. We have to look ahead.
- (ix). Equity, debt and reserves must get return.
- (x). The CSLA has confused between the IRR and Return on Capital. IRR is for choosing between projects. ROCE is for a particular project.
- (xi). Please do not have a rigid debt-equity ratio. A separate assessment with respect to each project is to be made.
- (xii). All infrastructure sector projects have the same fundamentals. They need large investments and returns are slow in coming. There is therefore no guarantee of returns. There has to be a guarantee of return. Otherwise, why will anyone invest?
- (xiii). Subsequent introduction of MAT has altered the position about tax holiday.
- (xiv). Depreciation of foreign equity over the life of the BOT concession has not been considered by the TAMP.

The Container Shipping Lines Association (CSLA)

- (i). It is good that the TAMP goes into these details.
- (ii). Please do not compare Private Terminals with Major Port Trusts. Even the return of 20% allowed to Private Terminals is high.

- (iii). A 20% return may be reasonable by 10/15 years of operation. To start with, it must be less.
- (iv). The model adopted in the NSICT case is liberal in giving a guaranteed tariff and a liberal return. It is charitable to the Terminal.
- (v). Please do away with the 'Cost-Plus' model. It is an uneconomic and un-commercial approach. Please do not isolate Private Terminal from commercial risks. This will work against efficiency.
- (vi). The NSICT's argument about comparing it with the Telecom Sector is not valid. Telecom is a high-risk technology; Ports are not in that category.
- (vii). Foreign exchange loss as a pass-through in tariff amounts to dollarisation
- (viii). The NSICT will ask for payment for efficiency. They have come in because of their international standing. They shall not charge extra for that.

Mumbai and Nhava-Sheva Shlp-Agents' Association (MANSA)

- (i). Free Reserves must also be considered along with equity.
- (ii). Major Port Trusts have no profit motive. But, Private Terminals have to pay dividend. So, consider them differently.
- (iii). Under Section 80-J of the Income Tax Act, 15% of Capital Employed was deducted. The Calcutta High Court has amended this provision to redefine Capital Employed to exclude long-term loans from the definition of Capital Employed.
- (iv). Debt-Equity ratio of 1:1 is very liberal. It appears that 2:1 may be more realistic.

Federation of Freight Forwarders' Association In India (FFFAI)

- (i). Comparison between a Major Port Trust and a Private Terminal is not valid at all. They are incomparable.
- (ii). Debt-Equity Ratio of 1:1 is very attractive.
- (iii). Why should reserve be considered for return. It must be deducted.
- (iv). Foreign exchange loss is a normal commercial risk.

Indian Merchant Chamber (IMC)

- (i). The objectives of Major Port Trusts and Private Terminals are different. They cannot be compared.
- (ii). Let Port pricing promote efficient service at cheaper cost.
- (iii). Trade risks cannot be grounds for increasing tariffs. The NSICT has come in knowing fully well the trade risks involved.
- (iv). Installed capacity has to be more than the demand. There cannot be a rigid match between the demand and supply.
- (v). The Private Terminals may give several benefits to Lines because of their efficiency. Nothing of that is passed on to the Trade. How does an efficient Private Terminal benefits the Trade in this situation?
- (vi). Uninhibited competition must be restricted. Huge investments already made must be protected to fetch adequate returns.

Jawaharlal Nehru Port Trust

- (i). The JNPT will be corporatised very soon. We will be commercial and we also need profit. We wish to maximise our ROCE.

7.1. The PSA SICAL reported its inability to participate in the joint hearing due to some crisis at its Tuticorin Terminal. Its request for filing a written submission within 10 days was allowed. Likewise, the request of the NSICT, CSLA, MANSA and ABG for time to file further written submissions was also granted. The NSICT also circulated a copy of the Arthur Andersen Report to the CSLA, MANSA, IMC and JNPT.

7.2. The salient points made in the written submissions filed by these organisations are summarised below:

I. The Nhava Sheva International Container Terminal Ltd

- (i). The Authority shall have confidence in the Balance Sheet Management of the private investors since none of the investors will be assuming a position that will harm the Company especially since global investors are involved.
- (ii). What the Authority must decide is if the capital employed is adequately reflective of capacity utilisation and if it is so then allow the prescribed return on capital employed to the Company.
- (iii). There are a number of benchmarks that can be used to determine a return. One of the best benchmarks on which return can be decided is Capital Employed for this is always adjusted year over year to reflect new investments and reduction in the existing investments. The Authority has rightly chosen this benchmark in the case of Port Trusts and should continue with this benchmark.
- (iv). The Authority has adopted 20% Return on Equity as a benchmark. If there is a tax holiday, the net return to foreign investor is only 9.08%. If there is no tax holiday, then the investor earns a return of only 4.5%.
- (v). The Authority should adopt a Return on Capital Employed in the region of 20% to 25% to Private Terminals.
- (vi). The question arose is whether the company operating a BOT is entitled to a Development Reserve and a Replacement Reserve. In the case of Companies under BOT projects these Reserves are crucial to the survival of the Companies. At the end of the License period these Companies hand over all their assets free of cost to the Port Trust and meet all employee liabilities and settlements as these employees are not absorbed by the Port. The Port gets equipment, which has a life of 20 years after being used for 7-10 years absolutely free. In such a case astute financial planning requires a company to have a reserve in place that will enable it to meet the heavy capital expenditure it is required to write off over less than half the useful life of assets. If double the depreciation is loaded (because the useful life for the BOT operator is limited) the tariffs of the operator will be commercially unviable thereby causing great financial loss. Thus, these stringent liabilities that the BOT operator faces must be spread out over a larger period so as to ensure the commercial viability of the project. The Authority must, therefore, consider allowing a percentage of the return earned as a reserve for development and replacement.
- (vii). The question arose whether debt : equity ratio of 1:1 is an appropriate ratio. The Authority must consider capital employed as the base for the return as rightly chosen by the Authority in the case of Port Trusts. In such a scenario the debt : equity ratio does not become applicable. Further, whilst shareholder funds are normally constant on account of no buy back of equity, debt is repaid based on the repayment schedule. In such a case debt will continue to reduce and thus the equity component will always increase in the ratio and when all debt is repaid only the equity component will remain.

The Authority must allow the private investor the freedom to decide on the financing pattern. It will not be detrimental to the interests of the company.

II. The PSA SICAL Limited

- (i). The TAMP has fixed a norm for debt to equity ratio as 1:1. The debt equity ratio may be different for different operators depending upon the private promoters' commercial requirement and the capability to leverage his funds. Hence, TAMP need not fix a norm for debt-equity.
- (ii). The TAMP has used capacity utilization as one of the factor of consideration. In the case of private terminals, adding new capacity is normally volume driven. Hence, the TAMP may allow flexibility while reviewing the business models of private operators.
- (iii). The TAMP has used 'pre-tax return' instead of 'post-tax return' as an indicator. If the tax payable is accounted for, the return on shareholder's funds will be reduced to as low as 14%, depending on the provisions of tax holiday. This is definitely inadequate to cover the business risk
- (iv). In fact, the 20% return on shareholders' funds and the interest on debt are inadequate to have sustained business operations.
- (v). In the long run, TAMP shall move away from the cost plus model to a competitive tariff model, especially for efficiently operated terminals. The cost-plus model is a disincentive for private operators with efficient operation and high asset utilization.

III. The ABG Heavy Industries Ltd.

- (i). Each terminal operator must be allowed to decide himself the combination of debt and equity in the capital structuring of the project. For the purpose of tariff fixation, it will not matter whether financing is done by means of debt or by raising equity. The entire cost of the project shall be reckoned as capital employed and 20% cost of capital should be considered for tariff fixation.
- (ii). Since the equity has no security of assets and is essentially fraught with uncertainties of risks and rewards, a return of 20% on the equity component of the capital employed shall be permitted over and above the cost of capital.
- (iii). If depreciation on straight-line method is adopted, this amount will be comparatively less in the first few years as against the amount of loan repayments. In our view, therefore, depreciation must be considered on written down value method whereby a larger amount of depreciation is available in the first few years, which will match with the corresponding amounts of repayment of principal.
- (iv). Whereas the interest on the debt is tax-deductible expenditure, return on equity is accounted from post-tax profits only. Therefore, an element of tax before return on equity needs to be factored in the tariff. This is particularly relevant from the point of limited applicability of tax holiday deductions under section 80 IA and tax on dividend distributions applicable to companies which are not applicable in the case of Port Trusts.
- (v). On the subject of capacity utilisation, what must be considered for tariff fixation is what is practically feasible in different phases of the life of the Port. Therefore, in the initial and formative years of the Project, capacity utilisation must be taken at not more than 50% of the rated capacity which can be progressively increased by 10% every five years until it reaches 90% capacity utilisation.

IV. The Container Shipping Lines Association

- (i). The CSLA is concerned that whatever earning benchmark is established, as a result of the lack of choice available, that benchmark level becomes the norm. The terminal

operator is thus effectively isolated from commercial risk (unless traffic flows fall away significantly, which seem unlikely) and is thus in the happy position of receiving a virtually guaranteed return. The CSLA prefers a regime such as that described by Arthur Andersen in paragraph 3.01 of its report which states, "In summary, while a uniform basis of rate determination is applied, certain parameters can be negotiated within pre-determined levels". There is no reason why the level fixed must become the basis for all pricing. Private Terminals shall be able to negotiate lower rates.

- (ii). Our investigation into the financials of NSICT (audited accounts for 9 months period ended 31/12/2000) reveals that the NSICT is currently earning (on an annualised basis) approximately 26% on shareholders' equity (where return=profit after tax+ technical service fees; royalty paid; and, shareholders equity = share capital + free reserves). This quantum of return on investment is considerably higher in comparison to the returns that will normally accrue to any capital-intensive industry. Hence, we fail to see why the NSICT is seeking a still higher return on its investment.
- (iii). Return on shareholders' equity is a sensible yardstick for regulating prices, where return shall be equal to 'Profit after tax' (adjusted for any royalty / technical service fee paid to any party) and Shareholders' equity should include Share Capital + Free Reserves & Surplus.
- (iv). The contention that private terminals and port trusts shall have the same regulation regime is reasonable, provided that they have the same obligations. It has to be recognised that Port Trusts have, by law, social and operational obligations which may not be the same, as for example, as the NSICT's obligations. The regime too must be equitable and market related. The returns allowed to the port trusts are too high. These need to be adjusted downwards and only then the same regime applied to both private and state terminals, subject to the observations made above. The return shall be limited to the Government lending rate to the Ports (which in the current year is 13%). No extra allowance shall be permitted for any other 'reserves'. This will mean that once the returns are higher than 13%, there will not be a need for the operator to approach the TAMP for an increase in tariff.
- (v). It is felt that the use of 'cost-plus' pricing mechanisms is entirely wrong. This places no onus upon terminals to be efficient. This will not serve the trade, or lines, or the country satisfactorily and will perpetuate commercial complacency and inefficiency.
- (vi). The NSICT and JNPT both face foreign currency debt, which can be forecast and anticipated. The Indian rupee has not been devalued exceptionally and, therefore, the exchange losses can be considered as the operators' commercial risk. It is also interesting that the TAMP has ruled against dollar denominated tariffs (except for certain cost categories). This proposal, removing as it does all the currency risk, is simply another means of achieving the same effect as a dollar denominated tariff.
- (vii). It is inappropriate to make comparisons with the telecommunications and power generation businesses. The former is a high risk, new technology business. Products have a relatively short "shelf life" and a high rate of return may, therefore, be justified. To equate this with the container terminal business which is old and well tried technology and is not a new industry, is inappropriate. Parallels with the power generation business are also inappropriate as this involves relatively few contracting parties, many of which are State organisations.
- (viii). It seems peculiar that the NSICT have apparently got their costings so wrong as to need a further change in the regulatory regime when they had a tariff approval in 1998 which presumably gave an adequate return, required a further change one year later, and now require further adjustments. No case has been made that costs have increased or other circumstances changed. Arthur Andersen say, rightly, that if costs increase, there must be a mechanism to recover them, provided, of course, that a justifying case is made so to do.

- (ix). Any increase granted will result in increased Terminal Handling Charges. It is incorrect though to suggest a fundamental failure here by the lines to pass back efficiencies to the trade. This is now happening by dint of the increased competition between lines which in turn is reducing freight rates, in the case of the European trade, dramatically, (1300 to 550 per TEU in 4 months). This competition would not have been possible without the efficiency of NSICT.
- (x). The P&O Ports have expressed the view in the past that they have been required to install cranes of a capacity that cannot be fully exploited as a result of draft restrictions. It is unfair to the NSICT if they have to carry the capital cost of such equipment. Equally, it is inappropriate for the lines and the trade to have to bear the cost of this equipment if indeed its full potential is unrealisable. It will be instructive to understand the utilisation of the NSICT equipment and the cranes in particular, to be sure that the amount of equipment is commensurate with the throughputs.
- (xi). 95% of the share capital of the NSICT is held by the P&O Ports, who then provide 'technical services' to the NSICT, effectively itself, for which it charges a fee. This appears to be largely a mechanism to maximise the profit taken from the NSICT. Having said this, it is inarguable that a terminal will probably require additional management expertise in its early stages of development, and indeed some specialist advice may be required from time to time thereafter. To suggest, however, that such services are required in perpetuity, and at these levels of remuneration seems inappropriate. The levels of advice required will reduce as the terminal matures, and while the Lines are not privy to the workings of the consultancy market the structure of the fee seems peculiar. It is not clear why this will be based upon the US consumer price index. It is also not clear why there will be fixed and variable elements. If a TSF is to be paid it shall be based upon management time or some other more related measure. It will be helpful to be able to debate the list of services provided, much of the items seemingly being more in the province of the management of the company in discharging their normal responsibilities than the province of consultants.

V. The Mumbai and Nhava-Sheva Ship- Agents' Association

- (i). The return shall always be measured in terms of the "capital invested" by the promoters. The tariff shall not cover the return on "capital employed" for a project, which the TAMP and Government have been providing 6% over and above the interest payable on "Long Term Loans".
- (ii). While, in the case of port trusts, return on 'capital employed' is considered for fixing the tariff, whereas in the case of private operators, the TAMP must ensure adequate return on the 'capital invested' by the promoters, and also include its General / Free Reserve, which is defined as 'Shareholders' Fund' / 'Net Worth'.
- (iii). Admittedly, there is a discriminatory treatment for fixing tariff, by considering return on the capital invested by the promoters in the case of private ports and return on the capital employed in the case of port trusts, as there is a difference in the basic financial structure in the case of port trusts and private ports. Profits of private operators can be distributed as dividends, while there is no such distribution in the case of Port Trusts. As allowing return on "capital employed" to Port Trusts itself is questionable, it should not be extended to private port operators.
- (iv). While Minimum Alternative Tax (MAT) has been made applicable to the NSICT, it has not been pointed out that under Section 80-IA, the deduction of 100% tax applicable to the NSICT is extended to 10 years, as against 5 years allowed earlier. Thus with frequent changes of provisions of incentives under the Income-Tax Act, it is advisable to consider return on pre-tax profit rather post-tax profit.
- (v). Prior to introduction of dividend distribution tax, dividend income was taxable in the hands of the recipient. The normal rate of tax on such dividend income would have been 35 to 40% and was much higher earlier. By introducing the above provision in 1997, the company is required to pay 10% tax on the amount of dividend declared and

the recipient of dividend is not taxed on such dividend income. Thus while the NSICT will have to pay tax on dividend declared, the recipient of dividend will not be taxed.

8.1. The joint hearing in this case was on the limited issue of 'return on capital employed'. But, many useful comments have been made by different parties even on other issues. These have been taken on record and retained for consideration separately, since, as earlier stated, the stated idea was to utilise the opportunity available for developing a common approach to tariff cases of all private terminals and not just with reference to the NSICT case under consideration.

8.2. Even on the limited issue of 'return on capital employed', it has to be recognised that the comments made have to be with reference to any 'error apparent on the face of the record' since the joint-hearing in respect of this case was about an application for 'review' of our Order. The comments that are relevant in this backdrop have been reckoned with in the context of our analyses recorded under each issue

8.3. The remainder of the comments have also been retained for consideration separately either for refining the existing models or for developing new models

8.4. The various issues agitated by the NSICT along with the advice given in the Arthur Andersen report and the arguments advanced at the joint hearing (on the limited issue of Return on investments) were analysed. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

I. Technical Service Fees

The Authority's Order

- (i). The BOT contract for development and operation of the container terminal has been awarded to the consortium lead by the P&O Australia based, *inter alia*, on the expertise and standing of the promoter. The NSICT was a later creation as envisaged in the concession agreement.
- (ii). The Technical Service Fee (TSF) has no linkage with the service provided. It is essentially a fixed payment more in the nature of dividend payable to the promoter. Prescription of a variable technical service fee as a percentage of profit and the practice of grossing up of taxes reinforce this understanding.
- (iii). No other similarly placed private terminal operator in any of the major ports has been following the practice of paying TSF to the main promoter
- (iv). The BOT agreement has been awarded based on the expertise of the promoter and the promoter is expected to pass on the expertise to the Indian company floated under the respective concession agreement.
- (v). The clearance stated to have been granted by the FIPB and the RBI can at best be seen as permissions to repatriate TSF payment while the propriety of such repatriation is not questioned, this payment cannot be recognised as a cost element for determination of tariff.
- (vi). The TSF payment is definitely in the nature of a return on capital employed and needs to be treated as a part of the return.

NSICT's Comments

- (i). The FIPB is not a remittance approval body. It approves such fees after proper application of mind. Incidentally, the FIPB comprises Secretary level officers from different ministries.
- (ii). TSF is not a dividend mechanism. The NSICT and P&O Ports are two separate legal entities. One's service cannot be available free to the other.

- (iii). If the stance taken by the TAMP is correct, then there is no difference between a financial investor and the investor who brings in technology.
- (iv). No legislation (e.g. Companies Act) has such a payment be deemed as dividend or return on capital.
- (v). TSF has approval of the Govt. of India.
- (vi). Our agreement has since been revised. Now, it is not necessary to gross up the TSF for tax.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). The other rate regulatory regimes in India do not specifically address the treatment of TSF payments. It may be inferred that the broad principles for allowing reasonable and justifiable business expenses in these regimes may apply to the treatment of TSF payment.
- (ii). Under the provisions of the Income Tax Act, TSF payment and tax borne on such TSF payment can be claimed as deduction by an Indian Company. The Income Tax authorities, however, can disallow tax deduction on that portion of the expenses which they believe to be excessive or unreasonable having regard to the market value of such services, the benefit derived and the legitimate need of the business.
- (iii). Approvals by the FIPB are based on negotiations and subjective analysis of various key factors. Negotiations with the FIPB are driven by business and commercial considerations, as well as benefits that accrue to the investor and the Indian economy.
- (iv). Where TSF payments are made under a technical service agreement approved by the FIPB, it is unlikely that the Income Tax authorities will disallow deduction on the ground that the payments are excessive or unreasonable. If the TSF payments are allowed by the Income Tax authorities, they may be considered as reasonable and justifiable business expenses by regulators and allowed for inclusion in cost based tariffs.

Analysis

The observation of M/s. Arthur Andersen about admissibility of TSF payment by default in other regulated sectors is presumptive and hypothetical. What effectively emerges from the report is that none of the other Regulators has explicitly admitted TSF payment as a cost pass-through in tariff.

Merely because TSF is considered as an admissible business expense by the Income Tax Authorities and is approved by the FIPB, it is not binding on a Regulator to allow it as an item of cost for determining tariff. Each of these Authorities draws up its own parameters for scrutiny of issues falling under its respective jurisdiction. It is a well-known fact that the method of arriving at depreciation varies between the Companies Act and Income Tax Act. In the case of the NSICT (which is a registered Indian Company), this Authority has allowed depreciation as per the Companies Act norms for determining tariff increase. This approach adopted by this Authority cannot be said to bind the Income Tax Authorities to assess depreciation in the same manner. Likewise, the approach adopted by other Authorities need not always be the sole guiding factor for this Authority.

It is noteworthy that this Authority had not declared the TSF payment as improper or illegitimate. It has clearly been mentioned that the propriety of repatriation of TSF payment is not questioned. This Authority has only decided not to recognise this payment as a cost element for determination of tariff for detailed reasons given in its Order. If the NSICT does not agree with the stand taken by this Authority in this regard, it has to agitate this issue in some other appropriate forum. Since there is no error apparent on the face of the record, review of our Order insofar as the issue of technical service fee is not necessary.

Incidentally, the NSICT has stated that the TSF is not now grossed up for tax. It is a welcome change. Revision of agreement between the NSICT and P & O Ports to this effect does not, however, alter the character of this transaction and, hence, its treatment in tariff determination.

II. Minimum Alternate Tax and Dividend Distribution Tax

The Authority's Order

- (i). There is no justification to consider the Dividend Distribution Tax as a cost element since it is in effect paid / payable on behalf of the shareholders and is akin to tax deduction at source.
- (ii). The rates of tax are subject to periodic changes and the outflow on account of tax is a function of the profit to be earned by the company. That being so, estimation of the liability of MAT beforehand for tariff setting may pose problems.
- (iii). It is appropriate to exclude the effect of taxation from net surplus estimation. If this is not done, adequate compensation by prescribing a higher pre-tax return on equity needs to be allowed.
- (iv). The TRAI does not consider the effect of taxation on the profit of Operators for determination of tariffs.

NSICT's Comments

- (i). Taxes are cost for the company when arriving at pricing decisions. The effect of taxation is always considered when fixing tariffs in all businesses.
- (ii). The Dividend Distribution Tax is neither a tax deducted at source nor a tax paid on behalf of the shareholders. The incidence of tax is on the company making the distribution and not on its shareholders.
- (iii). The Authority cannot ignore the fact that Major Port Trusts are not subject to payment of tax; but, the NSICT is liable to pay taxes.
- (iv). The TRAI has not made any reference to disallow taxes. Its orders dealing with the subject are prior to imposition of these taxes. 20% pre-tax return means 15.08% post-tax return to shareholders after a 10% transfer to reserves.

Comments of M/s. Arthyr Andersen

- (i). Under the provisions of the Income Tax Act, Dividend Distribution Tax is a tax cost for the company distributing the dividend for which credit cannot be claimed in India. As the recipient of the dividend is not entitled to claim credit for the DDT, it is not in the nature of the TDS by the company on behalf of the recipient.

Analysis

It is to be admitted that shareholders do not get credit for Dividend Distribution Tax (DDT) paid by the Company. They, however, do not pay any tax on the dividend received which they were paying before introduction of the DDT. In this context only it has been mentioned in our Order that the DDT is akin to Tax Deduction at Source (TDS). There is no confusion about payment of DDT being TDS. Only, such payment has to be recognised as shifting the incidence of tax from shareholders to the Company.

It is relevant here to point out that this Authority has allowed a pre-tax return on equity since taxes are not considered as cost pass-through in tariff.

The MANSA's observation about frequent changes in taxation is relevant and has already been recognised by this Authority. In this backdrop only, it was decided to allow a pre-tax return on equity.

The issue about admissibility of DDT and Minimum Alternate Tax may be relevant points for review; but, these issues had already been considered by this Authority in its Order dated 7 November 2000. The NSICT has not pointed out any errors apparent on the face of the record warranting a review. That being so, review of the Order with reference to admissibility of taxes is not necessary.

III. Foreign exchange losses

The Authority's Order

The NSICT claim for a return on investment on the foreign exchange loss pertaining to the unamortised foreign currency loans considering the variation of foreign exchange rate cannot be said to be correct. The NSICT can claim for the losses due to variation of foreign exchange rate only in respect of the foreign currency repayable during the year.

NSICT's Comments

- (i). Unrealised foreign exchange losses arising from foreign currency transaction which pertain to capital expenditure should be capitalised and depreciated over the remaining useful life of the estate as per the Indian Accounting Standard. The International Accounting Standard states that the unrealised foreign exchange losses are required to be charged to the profit and losses account.
- (ii). The NSICT has followed the practice as prescribed by the International Accounting Standard as it will reflect a true picture of the state of affairs.
- (iii). In the case of the approach followed by the Authority and given the NSICT's loan repayment pattern major exchange losses will arise and have an impact in year 7 of the loan thereby making the tariff fixation in that year unrealistic.
- (iv). The NSICT for arriving at tariff fixation is willing to adopt the approach prescribed in the Indian Accounting Standard. The Authority may reconsider its stand and approve this approach.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). The accounting treatment to be followed by Indian companies in respect of foreign currency transactions and resultant foreign currency position is prescribed by Accounting Standard 11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants, India.
- (ii). In terms of AS-11, where the foreign currency loan was applied for the purpose of acquisition of a fixed asset, the difference arising from restatement of loan is required to be adjusted in the carrying amount of the concerned fixed asset.
- (iii). The regulatory framework in other sectors provides two alternative bases for recognising exchange rate differences –
 - (a). at each year end in accordance with AS-11; or,
 - (b). at the time of repayment of loan.
- (iv). The AS-11 treatment will give a more accurate picture of the state of affairs of the entity. The AS-11 treatment will enable the entity to separate the effect of exchange rate depreciation over the treatment of loan.
- (v). Recognition of exchange rate differences on repayment can have potentially a large financial impact in a single year which can result in a sharp increase in cost base charges for consumers (if permitted by the regulator) or non-recovery of business related costs by the entity (if the regulator disallows pass through of the exchange losses).

- (vi). Since the treatment as per AS-11 will spread over the effect of exchange rate losses over the useful life of fixed assets, this approach will shield the customers from sharp and potentially volatile changes in the cost base.

Analysis

The NSICT being an Indian company is required to follow Indian Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. They have not, however, followed the AS-11. While submitting estimates along with their tariff revision proposal, the NSICT did not follow the Indian Standards and has charged the entire difference of restatement of loan to the P&L accounts as losses on account of foreign exchange fluctuation. This Authority had, however, allowed loss due to foreign exchange fluctuation on the instalment of loan repaid / repayable during the relevant years.

The report of M/s. Arthur Andersen specifically mentions that regulatory framework in other sectors provides for recognising exchange rate differences at the time of repayment of loan also.

The NSICT did not follow the Indian Accounting Standards; but, it has now requested this Authority to approve the Indian Accounting Standards so that it can adopt such a method. There is no need for this Authority to advise the NSICT on its accounting procedure. It has to maintain its accounts based on the system accepted for Indian companies. The NSICT was not advised by this Authority earlier to submit its estimates by methods other than the Indian Accounting Standard. Even the approach adopted by this Authority cannot be said to be wrong in the light of the comments furnished by M/s. Arthur Andersen.

If the NSICT revises its accounting procedure, this Authority may also consider appropriately for a prospective application at that time about treatment of loss on restatement of foreign currency loan for the purpose of determining tariff. Since this is relevant for future revisions, and considering the fact that a review cannot be made with reference to experiences gained or changes to be made subsequent to the Order, there is no merit in the NSICT argument for review of our Order with reference to the issue of foreign exchange loss.

Even though it is not directly relevant to this review petition, the CSLA's observation about dollarisation of tariff needs to be dealt with here to remove its misconception. Even in respect of those dollarised tariff items at the NSICT, the future income projections have been considered accounting for estimated appreciation of the US Dollar vis-à-vis the Indian Rupee. If this approach can be applied for Income projections, there is no reason why the same principle cannot be applied for estimating expenditure. There is a definite cash outflow due to loss in foreign exchange fluctuation relating to foreign currency loan repayment and this has been recognised in the cost estimates. Only in the case of equity, such method is not adopted since rate of return on equity has been fixed with reference to Indian capital market expectation. Considering the effect of foreign exchange fluctuations both in the estimates of income and expenditure can not be said to amount to 'dollarisation' of tariffs.

IV. Return on capital employed

The Authority's Order

- (i). The capital structure of the major ports and the private terminal operators are not similar.
- (ii). Development of an alternate approach relevant to BOT projects may have to be handled as part of a separate study with a long-term perspective. That being so, an interim approach has necessarily to be adopted to dispose off the NSICT proposal.
- (iii). The interim approach adopted is to allow the cost of respective sources of capital accepting the 1:1 debt equity ratio obtaining in the NSICT case.

- (iv). The cost of different sources of funds procured by the NSICT allowed as return on investment is as follows:
- (a). debt : actual interest payable during the year.
 - (b). Preference shares : the adopted rate of dividend payable i.e. 14%.
 - (c). Equity shares : The TRAI is considering 20% equity in return of equity for tariff setting. Studies conducted by experts e.g. CRISIL, Price Water House Cooper on the subject of cost of capital also pitch this figure at or around 20%. That being so, a return on equity of 20% is allowed.
- (v). The return on equity allowed is a pre-tax return.

NSICT's Comments

- (i). In the NSICT case, the Authority adopted a different approach deviating from the ROCE approach followed in the case of Major Port Trusts and other private operators. The interim basis adopted by the Authority is arbitrary and to the detriment of the NSICT.
- (ii). The Authority has not followed its own consultative approach principle in this matter and has thus not given an opportunity to the private investors to offer their views.
- (iii). Allowing a pre-tax return based on cost of capital to private terminals and post-tax return to Port Trusts based on capital employed is unfair and does not contribute to the overall objective of providing a level playing field among different operators.
- (iv). Cost of capital differs from return on capital. Return on capital involves an element of expected profit over and above the cost of capital.
- (v). NSICT has not had the privilege of relating to the studies conducted by the CRISIL and PWC. The Authority may share these findings with the NSICT.
- (vi). The cost of the debt of the NSICT is lower because this debt has been guaranteed by P&O Australia Ltd. By guaranteeing this debt without any charge to the NSICT, it is fair that the investor should be eligible to a return, which is being denied by the Authority.
- (vii). Retained earnings should be treated as component of shareholders' fund. These earnings are reinvested into the business. These retained earnings are a component of the net worth of the business and are entitled to a return.
- (viii). The Authority may review its interim approach and, till such time the Authority frames a transparent, objective and universally accepted principle, the NSICT may be allowed a return of 20% on capital employed.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). A reasonable return on capital will be that which has regard to the opportunity cost of funds and the business risks undertaken. The regulatory rate of return on capital is set, based on these considerations as well as the need to attract investment in the sector, the social and development objectives of the Govt. and other factors.
- (ii).
 - (a). In power transmission and distribution sector, 16% post-tax return is allowed on the capital base of fixing assets plus normative level of cash and stores less long term debt and special reserves.
 - (b). In the power generation sector, 16% post-tax return is allowed on equity and free reserves utilised for meeting capital expenditure of generation project. In case of foreign equity, 16% return is allowed in the currency of subscribed capital.

- (c). The TRAI allows a return of 25 – 30% on capital employed, which is a sum of net worth and debt investment in net worth component and related assets.
- (d). In case of the controlled bulk drugs manufacturing sector, the manufacturer can choose to apply for 22% pre-tax return on capital employed or 14% post tax return on net worth (net worth is the sum of equity and free reserves less outside investment; capital employed is the sum on net fixed assets and working capital).
- (iii). Foreign investors generally prefer some form of protection from the expected currency depreciation in the value of their investment. This can be achieved either through pass-through of the foreign equity arising on restatement of their equity or by indexation of the allowable return on the foreign equity to the US\$ / Indian rupee exchange rate. The latter approach has been allowed in the case of power generating companies in respect of foreign equity capital.
- (iv). Generally, investors prefer to earn a post-tax return to remove uncertainties arising from income tax regulations. An upward revision of income tax rate or introduction of a new tax when corresponding change in the allowable rate of return can adversely impact the return expectation of an investor in a rate regulated industry.

Analysis

It is true that this Authority veered away from the ROCE model adopted in the case of Major Port Trusts to a specific itemised return on respective sources of funds in the case of Private Terminal Operators. The deviation is made for reasons stated in paragraph 9 (xiii) of our Order. The method adopted is not arbitrary but with complete application of mind and reasoning.

The argument of the NSICT that the rate of interest on its borrowings is low because the P & O Australia has guaranteed the debt without any charge to the NSICT is not relevant. Scrutiny of the P & O Australia's bid for the Terminal was based on its financial standing. The NSICT was a later creation. The P & O Australia was expected to arrange for debt finance; and, there is nothing special that it has done which was not expected of it.

Retained earnings, as mentioned in the report of M/s. Arthur Andersen, are considered for allowing return in other sectors only if they are invested in the assets of the Project. This Authority has never held that retained earnings will not qualify for return. In the case of NSICT, even the debt and equity capital do not stand fully invested in the assets of the Project. That being so, the question allowing return on Retained Earnings does not arise at all.

Return on Preference share has been allowed at the rate adopted by the NSICT itself.

Equity shares have been allowed a pre-tax return of 20% which compares well with the ROCE of 19.5% (net of interest on loans) allowed in the cases of Major Port Trusts. The reasonable return on equity has been arrived at on the basis of capital market expectations reported by leading financial consultants in the country. The 20% pre-tax return on equity allowed works out to about 17% post-tax return according to the NSICT's own calculations. This cannot be claimed to be unfair or unreasonable when compared to the allowable return on equity in other sectors reported by M/s. Arthur Andersen. M/s. Arthur Andersen report that TRAI allows a 30% pre-tax return; the factual accuracy of this observation is not certain. The TRAI has indicated to us that it allows only a 20% return on equity, that too on an industry-specific assessment and not investor-specific. The TRAI allows an annual recurring expenditure @ 22% to 24% of capital investment. This includes a provision of 10% towards depreciation. It is to be recognised that in the case of the NSICT, depreciation has been allowed as a separate item of cost and over and above this a return on equity of 20% has been reckoned with.

The NSICT's argument about equity contribution from foreign investors and depreciation of Indian rupee allowing them a return of around 9% (with tax holiday) are irrelevant. It is to be recognised that 20% pre-tax return has been fixed with reference to Indian capital market expectations on Rupee investment. It is needless to mention that if the currency base is

changed, the rate of return is also to be adjusted. At this stage of development, it may be over optimistic to expect a return of 20% on US\$ equity. We are not sure whether (even) the US capital market offers such a level of return in infrastructure projects.

The issue of debt : equity ratio for a review is not relevant at all. The ratio of 1 : 1 has been allowed taking the position obtaining in the NSICT. It is true that the ratio will vary gradually with debt being serviced periodically. It is to be recognised that the cash inflow for such debt servicing is mainly from tariffs. This means the user is contributing towards repayment of loans also. That being so, a mere fact that loans have been serviced cannot alter the position as far as allowing a return is concerned. It is also to be recognised that allowing a return on investment based on the sources of capital without prescribing a prudential norm of capital mix cannot be said to be logical. While a Private Terminal can have a capital mix of its choice, the norm prescribed by this Authority will only be recognised for allowing Return on Investments.

It is to be admitted again that an opportunity was not given to the NSICT to put forth its views on the Return on Investment approach adopted. But, this lapse also has now been corrected by holding a joint hearing on this point at the MBPT on 3 September 2001. This opportunity was utilised for consulting the other concerned organisations for also developing a further refined model. Insofar as the review is concerned, the following two issues are relevant:

- (i). Whether the distinction made between the Private Terminals and Major Port Trust for allowing return is justified.
- (ii). Whether the quantum of pre-tax return on equity allowed is reasonable.

The issue about reasonableness of the return on equity allowed in the case of the NSICT has already been discussed elaborately in the foregoing paragraphs. The return allowed cannot be said to be unreasonable considering the Indian market conditions.

The capital structures of Private Terminals and Port Trusts do not compare. The old port trusts still report asset valuation (particularly, land) at historic cost based on valuation at the time of acquisition. There is no equity component in their structure. They do not distribute dividend; but, retained surplus is utilised for future development. They have also to create assets to fulfil social obligations. While the major ports finance assets through loans and internal resources, the private terminals raise funds through debt and equity. The cost of different sources of capital is easily identifiable in the case of private operators.

In spite of these differences, it has already been decided by this Authority to review the present method of allowing Return on Capital Employed for the Port Trusts. As has been pointed out by the CSLA, there is no justification in extending such a method, which essentially requires modification, to the Private Terminals. Significantly, the Private Terminal Operators like the PSA SICAL and the ABG have not suggested anything about applying the Return on Capital Employed model to them. They have only suggested some modifications in the model followed in the NSICT case. In view of the differentiation in the capital structures, different models of allowing return is justified in the cases of the Private Terminals and Major Port Trusts. As has already been mentioned, the matter relating to a review of the existing model for Major Port Trusts is progressing separately.

The comments offered by the CSLA and the MANSA do not suggest any change in the method adopted by this Authority.

In this issue, again, there is no error apparent on the face of the record. The NSICT has only challenged the approach adopted by this Authority in the case of Private Terminals deviating from the method followed in the cases of Port Trusts. The reasons for such deviations have already been elaborated in this Authority's Order dated 7 November 2000. If the NSICT does not agree with the approach adopted, it has to seek remedy from other forums. For these reasons, there is no need for this Authority to review its Order with reference to the approach adopted in this regard.

V. Capacity utilisation and return on equity**The Authority's Order**

- (i). Even though the NSICT has fully injected the capital required to achieve the capacity of 6.5 million TEUs (as envisaged in the Concession Agreement), the average capacity utilisation for the years 2000-01 and 2001-02 is around 82%.
- (ii). Not only in port projects, but in relation to investment in any project, the investors do not reasonably expect to get a return at the maximum right from the start.
- (iii). Only 80% of the maximum return on preference and equity shares, considering the average capacity utilisation of the terminal during the period under review, is allowed.

NSICT's Comments

- (i). The NSICT has guaranteed a traffic of 600000 TEUs per annum which is expected to be achieved in the 15th year of the concession period (Appendix X of the Concession Agreement).
- (ii). The NSICT while accepting the Authority's decision on restricting return to capacity utilisation requests to revise the figure of 6.5 million TEUs to 6.0 lakh TEUs per annum. Based on this figure the average capacity utilisation will be 89.43%.
- (iii). The Authority should adopt an approach of reward when additional investments over and above the required investments yield additional capacity.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). Capacity utilisation is a function of several demand and supply factors and some of the factors can sometimes be outside the control of the regulated entity.
- (ii). In the Telecom Sector, the TRAI has allowed basic and cellular service providers a return on capital investment without, prima facie, linking return to expected network capacity utilisation. Similarly, transmission and distribution utilities in Power Sector are allowed a return without reference to capacity utilisation.
- (iii). In the Power Generation Sector, while recovery of charges is linked to capacity, the following basis has been adopted:
 - (a). The base level for full recovery of fixing charges has been set through the tariff notification and committed in the power purchase agreement.
 - (b). Incentives are provided for availability over and above the base level.
 - (c). The utility is protected from non – off take of declared availability arising from certain events beyond its control.

Analysis

The Report of M/s. Arthur Andersen indicates that linking capacity with allowable return on investment for the purpose of tariff determination is in existence in the Power sector where tariffs are regulated. Even the NSICT itself has accepted the principle of linking return to capacity utilised.

Even though only a capacity of 6.5 lakh TEUs has been considered in our calculations; due to a typographical error it has been mentioned as 6.5 million TEUs in our Order. This typographical error does not, however, affect the calculation of the tariff increase. Nevertheless, this error will have to be corrected.

Even though the throughput guaranteed as per the Concession Agreement is 6,00,000 TEUs, the NSICT in its letter dated 3 August 2000 has indicated the capacity as 8.5 lakh TEUs after certain additional equipment are added. The 30-year projection given by the NSICT indicates a throughput of 6.5 lakh TEUs for 2002-03 rising to 8.5 lakh TEUs in 2005-06. That being so, there is no need to revise the percentage of capacity utilisation considered. On the contrary, if addition to the Capital Block projected for 2000-01 and 2001-02 is on account of acquisition of additional equipment to build a capacity of 8.5 lakh TEUs, the percentage of capacity utilisation considered earlier in our Order may have to be reduced.

It is relevant here to mention that if the NSICT wants to stick to the capacity envisaged under the CA, then the quantum of capital investment to be considered for tariff purposes should also be linked to the requirements stipulated thereunder. There is no doubt that the NSICT has added more number of equipment and created additional facilities than those given in the CA. It will be a mismatch to the level of being called a blunder if actual investment made is considered along with the minimum level of capacity envisaged in the CA.

VI. Deduction of excess cash

The Authority's Order

- (i). The estimates furnished by the NSICT show a huge cash and bank balance during the year 2000-01. This balance is far in excess of reserve funds.
- (ii). Since excess cash holding represents idle capital, the cash balance in excess of reserve funds is excluded while reckoning with the return on preference and equity share.

NSICT's Comments

- (i). The Authority has deducted the excess cash based on the NSICT application for a 30% tariff increase without considering the effect of reduced tariff level approved, the tax and dividend paid out.
- (ii). The cash balance should be re-worked based on 16% increase approved and then arrived at considering the impact of payment of taxes and dividends to the share holders.
- (iii). Considering the year end cash balance is not a true reflection of the correct position, the better practice will be to adopt an average of opening and closing balances of cash to ensure equalisation.
- (iv). Cash balances do not earn return exceeding 8% at the maximum flows with fix deposit in banks. The NSICT suggests that an interest earning at 10% on cash balance be adopted by the Authority of 65% of the average cash balance, which will reflect an adequate return on cash.

Analysis

Since the year-end balances of debt and equity have been considered for allowing return, deduction of year-end unutilised cash balance is in order. In the long run, considering average balance or year-end balance may not make any material difference. Incidentally, closing balance of capital employed including working capital is considered in the case of Major Port Trusts also.

The amount of unutilised cash balance deducted is in fact based on the indications given by the NSICT in the 30-year projection, which assumes a 30% increase in tariff as per tariff application. This may become less with the 16% increase allowed. However, this may not materially affect the increase in tariff allowed as the percentage of revision allowed is higher than the actual deficit disclosed by the cost statement. Further, reduction of excess cash balance is not a new practice adopted by this Authority only in the case of the NSICT. The

figure of working capital has been moderated to a reasonable level in the cases of tariff revision of many of the Major Port Trusts.

The issues raised by the NSICT for allowing 8% interest on cash balance, etc., are not relevant. It is to be recognised that in the case of the NSICT, this Authority did not adopt the conventional method of determining return on capital employed (Fixed Assets + Working Capital). The return allowed for the NSICT was with reference to sources of fund; and, in this context, excess cash reflected funds not invested in operation and, was therefore, deducted. This approach has only been adopted for the purpose of determining tariff. This does not mean this Authority has not recognised the ability of Balance Sheet Management of the NSICT.

VII. 30-year period analysis

The Authority's Order

- (i). The 30-year analysis made keeping the tariffs constant is not appropriate.

NSICT's Comments

- (i). The calculations, as mentioned in the Order, are only theoretical and hypothetical as rightly observed by the Authority.
- (ii). The Authority should review each application for the 2-year period as prediction. Estimates for a 30-year period really serve no purpose in pricing decision. These decisions apart from demand and supply are also influenced by macro-economic factors.

Analysis

The tariff increase allowed in the NSICT case is based on projections for the following two years considered at that time. The 30-year analysis is only an aid to the decision-making process as it can throw up some meaningful indicators (for instance, in this case, the capacity of the Terminal). The observation of the NSICT in this regard is general in nature and does not warrant a review of our Order.

VIII. Adjustment in future tariff

The Authority's Order

The tariff and income projections furnished by the NSICT have been relied upon without any modifications. If this approach seems to have given any undue advantage to the Terminal Operator, at the time of review during the next revision of tariffs, any undue benefit accrued to the terminal operator will be set off against the future revision of tariffs.

NSICT's Comments

The Authority should also accept the principle that adverse changes which affect the financial stability and return of the NSICT will also be considered.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). As cost based tariffs are developed from estimates of cost, changes in actual costs of given inputs can adversely impact the financial position of the regulated entities and the sector as a whole.
- (ii). In some sectors, such as power, the regime has a mechanism to compensate utilities for justifiable increase in fuel cost over previously projected levels either through indexation mechanisms or future tariff revisions.

Analysis

If any of the planning premises undergoes adverse change with reference to the estimates made by the Operator, he will always have the option to seek an ahead-of-schedule tariff adjustment. Incidentally, the November 2000 revision of the NSICT tariff was an ahead-of-schedule one which was allowed based on the NSICT's plea for having its tariff with reference to its own cost of operation instead of continuing with the rates adopted from the Jawaharlal Nehru Port Trust's Scale of Rates.

If variations in the estimates are favourable to the Operator, it is likely that he may not come up with a proposal to review the approved tariffs in the context of the benefit accrued to him on account of such variations. It was in this backdrop that the reference was made about such advantages being set off against future accruals.

In any case, this issue does not affect the tariff increase allowed in November 2000. That being so, it is not relevant for a review of the Order.

IX. Application of a uniform basis of tariff determination for different Operators

NSICT's Comments

- (i). The Authority has always stated and maintained that its approach towards tariff fixation will be a consultative process. NSICT supports this stand in this matter but request that it may also be given a similar opportunity to make representations when the Authority departs from the established practices.
- (ii). In the impugned Order, the Authority has implemented a whole new set of financial parameters on which the NSICT has never been asked for its representation. The Authority has also implemented the scheme (ELT) on which the NSICT was not asked for its views.
- (iii). The Authority should adopt an approach which is practical. Such an approach should also consider realities and also practices prevalent in the industry. Till date, the TAMP in general followed accepted principles in the case of major ports, but has chosen to deny benefits of dollar tariff to the NSICT and further impose an ELT scheme which is far more stringent than the Concession Agreement requirements and also adopt financial parameters for evaluating the NSICT proposal which are not universally used parameters.

Comments of M/s. Arthur Andersen

- (i). In general, the TAMP has applied a uniform set of parameters across all operators / Port Trusts.
- (ii). In some instances, however, the TAMP appears, prima facie to have adopted a different basis in the determination of cost base charges for other ports / operators vis-à-vis the NSICT. The differences relate to
 - (a). Allowing other operators a return on total capital employed as opposed to a return on paid up capital for NSICT.
 - (b). Reducing the NSICT's return on capital to the extent of estimated capacity utilisation.
 - (c). Linking NSICT's charges to tariffs in terms of moves per hour.

These differences have the effect of reducing NSICT's cost base / allowable return for development of cost base charges.

Out of the three issues mentioned by M/s. Arthur Andersen, the point about ELT scheme has lost its relevance now since this Authority has already rescinded the ELT Scheme introduced vide our Order dated 7 November 2000. The other issues have been dealt with in the analysis given under the respective heads.

9. In the light of the analysis given above there is no error apparent on the face of the record warranting a review of our Order dated 7 November 2000. As has already been mentioned, the issues agitated by the NSICT are in support of a totally new approach to tariff setting in the case of the Private Terminals. That is a different matter altogether. The approach adopted by this Authority in the case of the NSICT does not require any modification with reference to the points agitated. If the NSICT is not satisfied with the approach adopted by this Authority, it has to approach other appropriate forums for redressal of its grievances. That being so, this Authority does not find it necessary to review and modify the approach already prescribed by it in the NSICT case.

10. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority rejects the application of the NSICT for a review of this Authority's Order dated 7 November 2000 relating to revision of its tariff.

11. Notwithstanding the decision not to review the earlier Order dated 7 November 2000 in this case, this Authority, nevertheless, recognises some issues arising out of this proceeding need to be addressed further for refining the approach adopted for prospective application. The Port Sector in our country is undergoing a transition in the sense that private terminals have begun to emerge in a big way. New models will have to be developed to suit emerging requirements. In any transition situation, this will have to be a continuing exercise for sometime; it will not be reasonable to expect readymade solutions for immediate adoption.

S. SATHYAM, Chairman
[No. ADVT/143/Extra-2001]

